वर्ष 17
अंक 27
8 पृष्ठ
मूल्य 5 रुपये

सोमवार, 18 मार्च 2024
कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, भोपाल, मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड

▸▸ पृष्ठ 2

चीन को छोड़ भारत पर ध्यान दे रहीं वैश्विक खिलौना फर्में

नरेंद्र मोदी ▸▸ पृष्ठ 8

100 दिन के कामकाज की रूपरेखा बनाएं मंत्री

एक नज़र

फ्यूचर गेमिंग ने द्रमुक को दिया सबसे ज्यादा चंदा

फ्यूचर गेमिंग ऐंड होटल सर्विसेज ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक (डीएमके) को सबसे ज्यादा 509 करोड़ रुपयों का चंदा दिया। 'लॉटरी किंग' सेंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग 1,368 करोड़ रुपयों के साथ चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार थी, जिसमें से लगभग 37 फीसदी द्रमुक को गया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से रविवार को यह जानकारी सामने आई। भारतीय जनता पार्टी को 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना के लागू होने के बाद से सबसे अधिक 6,986.5 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, इसके बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (1,397 करोड़ रुपये), कांग्रेस (1,334 करोड़ रुपये) और बीआरएस (1,322 करोड़ रुपये) का स्थान रहा। पृष्ठ 8

फेड के रुख से तय होगी शेयर बाजार की दिशा

शेयर बाजार की दिशा इस हफ्ते अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय से तय होगी। इसके अलावा वैश्विक बाजारों का रुख और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भी बाजार के लिए महत्त्वपूर्ण रहेंगी। पिछले सप्ताह छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट, विदेशी कोषों की निकासी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हफ्ते दुनिया के कई केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति पर अपने रुख की घोषणा करेंगे। ऐसे में निकट अवधि में शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रह सकता है। फेडरल रिजर्व 20 मार्च को ब्याज दरों पर अपने निर्णय की घोषणा करेग। बैंक ऑफ जापान 19 मार्च को ब्याज दर पर अपने निर्णय की घोषणा करेगा। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।

क्विक कॉमर्स में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा

अस्थायी शुरुआत करने के बाद क्विक कॉमर्स (क्यू-कॉमर्स) चमक रहा है। ब्लिंकइट और जेप्टो इसे बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में जुटी हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली नई कंपनी फ्लिपकार्ट है। वह लगभग 12 शहरों में अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। यहां वह अगले छह से आठ सप्ताह में ब्लिंकइट, जेप्टो, इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसी मौजूदा कंपनियों को टक्कर देते हुए सेवा शुरू करेगी। पृष्ठ 2

आज का सवाल

क्या चुनावों में सरकारी फंडिंग को प्रोत्साहित करने के हों उपाय?

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **Y** और यदि न है तो **N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा
क्या चुनावी बॉन्डों के खुलासे से कंपनियां होंगी हतोत्साहित?
हां 65% | नहीं 35%

बिज़नेस स्टैंडर्ड के सर्वेक्षण में सीईओ की राय

चुनावी बॉन्ड विवाद से बेअसर रहेंगे मतदाता

बीएस संवाददाता
मुंबई/नई दिल्ली/ कोलकाता/ चेन्नई, 17 मार्च

चुनावी बॉन्ड पर हाल में उठे विवाद का मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आगामी लोक सभा चुनाव के नतीजे भी इससे बेअसर रहेंगे। ये बातें बिज़नेस स्टैंडर्ड के एक सर्वेक्षण में सामने आई हैं। इस सर्वेक्षण में 10 मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) से चुनावी बॉन्ड पर उठे विवाद पर उनकी राय पूछी गई।

इन सीईओ ने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कंपनियों एवं लोगों के नामों के खुलासे से मतदाता प्रभावित नहीं होंगे और न ही इससे लोक सभा चुनाव के नतीजों पर ही कोई असर पड़ेगा। जब इन सीईओ से नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाजी प्रदर्शन एवं विकास कार्यों पर उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने 1 से 5 (एक सबसे कम और 5 सबसे अधिक) के पैमाने पर औसतन 4.1 रेटिंग दी। एक सीईओ ने मोदी सरकार को 3 रेटिंग दी जबकि दो ने मोदी सरकार के प्रदर्शन एवं विकास कार्यों को 5 में 5 रेटिंग दी।

एक सीईओ ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, 'पिछले पांच साल चुनौतीपूर्ण रहे हैं। मगर जब वैश्विक हालत के बरअक्स देखेंगे तो भारत का प्रदर्शन कहीं बढ़िया रहा है। इसे देखते हुए मैं मोदी सरकार को 5 में 5 रेटिंग से नवाजूंगा।'

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सीईओ में 30 प्रतिशत ने कहा कि कंपनियों से एवं निजी स्तर पर चंदा लेने से बचने के लिए चुनाव खर्च के लिए सरकारी स्तर पर ही प्रावधान किया जाना चाहिए। मगर इतने ही सीईओ इस तर्क से सहमत नहीं हुए। 40 प्रतिशत ने चुनाव पर होने वाले खर्च के लिए सरकारी स्तर पर प्रावधान किए जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। एक सीईओ ने कहा, 'राजनीतिक दलों एवं कंपनियों दोनों के लिए चंदे की जानकारी देना अनिवार्य होना चाहिए। कंपनियों की सालाना रिपोर्ट में इससे जुड़ी जानकारियां स्पष्ट रूप से शामिल होनी चाहिए और सभी दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग को इनकी जानकारियां देनी चाहिए।'

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले आधे सीईओ ने कहा कि राजनीतिक चंदे के विषय पर उनके निदेशकमंडल (बोर्ड) में कोई स्वीकृत नीति नहीं है। 40 प्रतिशत का कहना था कि उनके बोर्ड में राजनीतिक चंदे पर मंजूरी ली जाती है। उपभोक्ता उत्पाद (कंज्यूमर प्रोडक्ट्स) बनाने वाली एक कंपनी के सीईओ ने कहा, 'चुनावी खर्च के लिए मिलने वाली रकम को लेकर थोड़ी और पारदर्शिता की जरूरत है। हमें इस मामले में पश्चिमी देशों से सबक लेना चाहिए।'

अजय मोहंती

सर्वेक्षण में दिग्गज सीईओ ने कहा...

प्रशासन और विकास के लिहाज से पिछले 5 साल को आप 1 से 5 के बीच कितनी रेटिंग देंगे? 1 सबसे कम और 5 सबसे अधिक है।
औसत रेटिंग : 5 में से 4.3

क्या आपको लगता है कि चुनावी बॉन्ड का मसला आगामी आम चुनाव में मतदाताओं पर असर डालेगा?
हां : 0 फीसदी नहीं: 100 फीसदी
मालूम नहीं : 0 फीसदी

क्या आपको लगता है कि कंपनियों/निजी चंदे पर रोक के लिए चुनावों में सरकारी रकम को प्रोत्साहित करना चाहिए?
हां : 30 फीसदी नहीं: 30 फीसदी
मालूम नहीं : 40 फीसदी

क्या आपके पास राजनीतिक चंदे के लिए बोर्ड से मंजूरी की कोई नीति है?
हां : 40 फीसदी नहीं: 50 फीसदी
मालूम नहीं : 10 फीसदी

स्रोत : बीएस सीईओ सर्वे

इन सीईओ से यह भी पूछा गया कि अगले पांच वर्षों में उन्हें सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। इस पर सीईओ ने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाने, रोजगार सृजन और लघु एवं मझोले उद्यमियों के लिए अधिक समर्थन देने के उपाय करने चाहिए।

(मुंबई से देव चटर्जी, शार्लीन डिसूजा, सोहिनी दास, राघव अग्रवाल, कोलकाता से ईशिता आयान दत्त और चेन्नई से शाइन जैकब)

वाहन कंपनियों की नजर गांव-देहात पर

सोहिनी दास
मुंबई, 17 मार्च

- पिछले कुछ वर्षों में गांव-देहात में अधिक बिके हैं यात्री वाहन
- शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री में हुआ है इजाफा
- 2024-25 में बिक्री 3 से 5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद
- वाहन कंपनियां ग्रामीण इलाकों में कारोबार फैलाने में जुटीं

पिछले कुछ वर्षों में गांव-देहात में शहरों के मुकाबले ज्यादा यात्री वाहन बिक रहे हैं। यह देखकर यात्री वाहन कंपनियां छोटे शहरों एवं नए बाजारों में कारोबार फैलाने में जुट गई हैं। वाहन उद्योग का अनुमान है कि वर्ष 2024-25 में यात्री वाहनों की बिक्री औसतन 3-5 प्रतिशत बढ़ सकती है। इस उद्योग के प्रतिनिधियों के अनुसार गांव-देहात में यात्री वाहनों की बिक्री परवान चढ़ते देख वहां कारोबारी तंत्र का विस्तार करना जरूरी हो गया है। वर्ष 2023-24 में यात्री वाहनों की कुल बिक्री 42 लाख रहने का अनुमान है।

मारुति सूजुकी इंडिया में वरिष्ठ कार्याधिकारी (प्रचार एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव कहते हैं, 'पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्र की तुलना में यात्री वाहनों की बिक्री अधिक रही है। कोविड महामारी के दौरान जब शहरी इलाकों में बिक्री की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था तब गांव-देहात में ऐसे वाहनों की बिक्री फर्राटा भर रही थी। यात्री वाहनों की कुल बिक्री की बात करें तो इसका लगभग 32-33 प्रतिशत हिस्सा गांव-देहात झटक लेते हैं। मतलब साफ है कि हमें देश के ग्रामीण इलाकों में अपना कारोबार फैलाने पर अब औरअधिक ध्यान देना होगा।' इस समय मारुति की 45 प्रतिशत कारें गांव-देहात में ही बिकती हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 2018-19 में आंकड़ा लगभग 38 प्रतिशत रहा था।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'वित्त वर्ष 2024 में टाटा मोटर्स की कारों की बिक्री वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 5 गुना अधिक रही है। इनमें गांव-देहात में बिक्री 40 प्रतिशत तक रही है।'

चंद्रा ने कहा कि ग्राहकों के करीब पहुंचने के लिए कंपनी ने बिक्री एवं मरम्मत आदि सुविधाएं तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने ऐसे 800 से अधिक केंद्र (आउटलेट) स्थापित किए हैं जो आस-पास के शहरों के करीब हैं और विशेष तौर पर ग्रामीण ग्राहकों को अपनी सेवाएं देते हैं। चंद्रा ने कहा कि कंपनी ने 135 अनुभव वैन (मोबाइल शोरूम) भी स्थापित किए हैं।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा में मुख्य कार्याधिकारी (ऑटोमोटिव सेक्टर) नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, 'ग्रामीण क्षेत्रों में अब सड़क सुविधाओं का काफी विकास हुआ है। सड़कें सुधरने के बाद अब हम कारोबार फैलाने की योजना आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ग्राहकों को आसानी हो। इससे हमें भी कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।'

गोलागुंटा ने कहा कि देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही इलाकों में कंपनी की एसयूवी की बिक्री लगातार बढ़ रही है। अलबत्ता गांव-देहात के लिए यात्री वाहन कंपनियां थोड़ी अलग रणनीति अपना रही हैं। श्रीवास्तव ने कहा, 'देश के ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों की पसंद-नापसंद समझनी पड़ती है और उनकी भावनाओं को भी समझना पड़ता है। डीलरों को नए ग्राहक बनाने के लिए लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ना पड़ता है। वाहन कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करती हैं और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ने को कोशिश कर रही हैं।'

देश में 6.50 लाख गांव हैं और इनमें 4.10 लाख गांवों में कम से कम एक मारुति कार है। श्रीवास्तव ने कहा कि मारुति के पास अब भी 2.50 लाख गांवों में पहुंचने की गुंजाइश बची हुई है।

स्टार्टअप महाकुंभ: आशा और विविधता का संगम

आर्यमन गुप्ता
नई दिल्ली, 17 मार्च

राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में भारत मंडपम स्टार्टअप कंपनियों के महाकुंभ की मेजबानी करने जा रहा है। वहां सोमवार से शुरू हो रहे तीन दिन के स्टार्टअप महाकुंभ के दौरान भारत की ये कंपनियां दुनिया भर में सुर्खियां बटोरेंगी।

पीक 15 के प्रबंध निदेशक रंजन आनंद ने कहा, 'भारत आज हर क्षेत्र में नवोन्मेष कर रहा है और दुनिया के लिए भी नवाचार ला रहा है। हमने निर्णायक बिंदु पार कर लिया है और भारत पहले ही दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप तंत्र वाला देश बन चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को अपनी क्षमता दिखाएं।' यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब स्टार्टअप क्षेत्र के लिए निवेश का सूखा खत्म होने की उम्मीद जगी है। 2023 में भारतीय स्टार्टअप में आने वाला निवेश 72 फीसदी घटकर 7 साल में सबसे कम रहा। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान स्टार्टअप को महज 7 अरब डॉलर का निवेश मिला, जबकि 2022 में 25 अरब डॉलर का निवेश हुआ था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा, 'आज स्टार्टअप तंत्र के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है। नवोन्मेष के मामले में भारत दुनिया में 40वें स्थान पर है और हमारा लक्ष्य इससे आगे बढ़ना है। हमारा उद्देश्य स्टार्टअप महाकुंभ को न केवल बड़ा आयोजन बनाना है बल्कि इसे वार्षिक आयोजन बनाना है, जो भारतीय स्टार्टअप तंत्र के विकास को गति दे सके।'

कार्यक्रम में 50 यूनिकॉर्न और 500 इन्क्यूबेटर सहित 1,000 से अधिक स्टार्टअप एवं निवेशक शामिल होने की उम्मीद है। 23 देशों के 5,000 प्रतिनिधिमंडल और 50,000 कारोबारी आगंतुक भी इस महाकुंभ में शिरकत कर सकते हैं। आयोजन समिति के सदस्य और केकेआर इंडिया के पूर्व सीईओ संजय नायर ने कहा, 'यह आयोजन दुनिया को दिखाएगा कि भारतीय स्टार्टअप तंत्र परिपक्व हो गया है। यह स्टार्टअप को पूंजी निवेश करने वालों से जुड़ने का भी मौका दे रहा है।' आयोजन का मुख्य विषय 'भारत इनोवेट्स' है और इसमें मेंटॉरशिप क्लीनिक, पिच प्रतिस्पर्धाएं तथा मल्टी-ट्रैक जैसे कार्यक्रम होंगे, जिसमें लीडरशिप चर्चा, समूह परिचर्चा, कार्यशालाएं और स्टार्टअप के साथ ही भावी उद्यमियों की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। नायर ने कहा कि इसमें न केवल महानगरों के स्टार्टअप शामिल होंगे बल्कि देश भर के छोटे-मझोले शहरों और जिलों के भी कई स्टार्टअप इसमें शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि एक यह व्यापक मंच है जिसमें स्टार्टअप को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है।

उद्योग संगठनों एसोचैम, नैसकॉम, बूटस्ट्रैप इन्क्यूबेशन और एडवाइजरी फाउंडेशन, टीआईई तथा इंडियन वेंचर ऐंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन की अगुआई में यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम की विविधता को प्रदर्शित करेगा। एस्सेल में पार्टनर प्रशांत प्रकाश ने कहा, 'हम जिस क्षेत्रीय विविधता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वह भारतीय स्टार्टअप तंत्र का महत्त्वपूर्ण पहलू है।'

स्टार्टअप का जमावड़ा

- नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोमवार से शुरू होगा तीन दिन का स्टार्टअप महाकुंभ
- विभिन्न क्षेत्रों के 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप दिखाएंगे अपनी क्षमता
- दुनिया भर के निवेशकों और 23 देशों के प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद

संक्षेप में

भारत में निवेश तेज करेगी डीकैथलॉन

फ्रांस की खेल क्षेत्र की खुदरा कंपनी डीकैथलॉन अपने 'सबसे महत्वपूर्ण' वैश्विक बाजारों में से एक भारत में उत्पादन और खुदरा पहुंच को और बढ़ाने के लिए निवेश में तेजी ला रही है। कंपनी की वैश्विक मुख्य कार्य अधिकारी बारबरा मार्टिन कोपोला ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि डीकैथलॉन को भारतीय बाजार से अपनी 'उच्च वृद्धि दर' जारी रहने की उम्मीद है। भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी भारत से अपने उत्पादन का 65 प्रतिशत वैश्विक बाजारों को निर्यात करती है। उन्होंने कहा कि डीकैथलॉन के लिए भारत वर्तमान में शीर्ष 10 वैश्विक बाजारों में से है, जो दूसरों की तुलना में 'दोगुनी दर' से बढ़ रहा है। *भाषा*

कर्मियों की संख्या 350 करेगी 'फ्लाई91'

क्षेत्रीय एयरलाइन 'फ्लाई91' 18 मार्च से अपनी वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने जा रही है। एयरलाइन ने कहा है कि परिचालन के पहले साल के अंत तक उसके कर्मचारियों की संख्या 350 हो जाएगी। कंपनी का लक्ष्य दो साल में लाभ की स्थिति में आने का है। गोवा की इस एयरलाइन के बेड़े में वर्तमान में दो एटीआर 72-600 विमान हैं। परिचालन के पहले साल में एयरलाइन चार और विमान जोड़ेगी। फ्लाई91 के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्य अधिकारी मनोज चाको ने कहा कि अब कोष जुटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान' के तहत परिचालन को व्यवहार्य (वीजीएफ) बनाने के लिए वित्तपोषण मिलेगा। उन्होंने कहा, 'हमें जो क्षेत्र मिले हैं उनके लिए हमारे पास वीजीएफ है। अगर हम उन सभी क्षेत्रों को लें जिन्हें हमने हासिल किया है और अगर हम पूरी सारिणी संचालित करते हैं तो सालाना आधार पर यह करीब 200 करोड़ रुपये होगा।' *भाषा*

फ्लिपकार्ट को दो साल के दौरान लगी बड़ी चोट

मूल्यांकन 41,000 करोड़ रु घटा

भाषा
नई दिल्ली, 17 मार्च

ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन दो साल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 41,000 करोड़ रुपये घट गया है। इसकी अमेरिकी स्थित मूल कंपनी वॉलमार्ट के इक्विटी लेनदेन से यह जानकारी मिली है।

फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट के इक्विटी ढांचे में बदलाव के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनी का मूल्यांकन 31 जनवरी, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में 40 अरब डॉलर था, जो 31 जनवरी, 2024 को घटकर 35 अरब डॉलर रह गया। फ्लिपकार्ट ने मूल्यांकन में गिरावट की वजह वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी फोनपे को अलग कंपनी के रूप में विभाजित करना बताया है।

सूत्रों का हालांकि कहना है कि फ्लिपकार्ट का मौजूदा मूल्यांकन 38-40 अरब डॉलर के बीच है। वॉलमार्ट ने वित्त वर्ष 2021-22 में फ्लिपकार्ट में 8 फीसदी हिस्सेदारी को 3.2 अरब डॉलर में बेचा था। इस हिसाब से ई-कॉमर्स कंपनी का मूल्यांकन 40 अरब डॉलर बैठता है। वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिकी खुदरा क्षेत्र की दिग्गज ने 3.5 अरब डॉलर का भुगतान कर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 10 फीसदी बढ़ाकर 85 फीसदी कर दी। इसके आधार पर फ्लिपकार्ट का उद्यम मूल्य 35 अरब डॉलर बैठता है।

हालांकि, फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट की रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन में दिखाई गई कमी को खारिज करते हुए कहा है कि यह कंपनी के मूल्यांकन में 'उचित समायोजन' की वजह से है।

फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा, 'यह व्याख्या गलत है। फोनपे को अलग करने का काम 2023 में पूरा हुआ था। इससे फ्लिपकार्ट के मूल्यांकन में उचित समायोजन हुआ। फ्लिपकार्ट के सूत्रों ने कहा कि उद्यम का मूल्यांकन आखिरी बार 2021 में किया गया था और उस समय ई-कॉमर्स कंपनी के कुल मूल्य में फिनटेक फर्म फोनपे का मूल्यांकन भी शामिल था।

मानसिक यातना के मामले में फ्लिपकार्ट को 10 हजार रुपये चुकाने का आदेश

एजेंसियां
मुंबई, 17 मार्च

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट को अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने का दोषी पाया है और आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 10,000 रुपये का भुगतान करे क्योंकि आईफोन का ऑर्डर रद्द करने पर ग्राहक को मानसिक यातना झेलनी पड़ी।

यह ऑर्डर अतिरिक्त मुनाफा कमाने के इरादे से रद्द किया या था, जो कंपनी की तरफ से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ये बातें कही और आयोग ने पिछले महीने यह आदेश जारी किया था। इस आदेश की विस्तृत ब्योरा रविवार को उपलब्ध हुआ।

आयोग ने पाया कि ग्राहक को हालांकि रिफंड मिल गया, लेकिन उसे जो मानसिक यातना झेलनी पड़ी, उसके लिए उसे मुआवजे की दरकार है क्योंकि यह ऑर्डर एकपक्षीय तौर पर रद्द कर दिया गया था। दादर निवासी की शिकायत के मुताबिक, उसने 10 जुलाई 2022 को आईफोन का ऑर्डर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से दिया था और क्रेडिट कार्ड से 39,628 रुपये का भुगतान किया था।

क्विक कॉमर्स क्षेत्र में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 17 मार्च

अस्थायी शुरुआत करने के बाद क्विक कॉमर्स (क्यू-कॉमर्स) चमक रहा है। ब्लिंकइट और जेप्टो इसे बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में जुटी हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली नई कंपनी फ्लिपकार्ट है। वह लगभग 12 शहरों में अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। यहां वह अगले छह से आठ सप्ताह में ब्लिंकइट, जेप्टो, इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसी मौजूदा कंपनियों को टक्कर देते हुए सेवा शुरू करेगी।

बोफा ग्लोबल रिसर्च द्वारा सेंसर टॉवर के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार फरवरी 2023 और फरवरी 2024 के बीच ब्लिंकइट का दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता आधार 58 प्रतिशत बढ़ चुका है। हालांकि जेप्टो कहीं अधिक आक्रामक रही है और इस अवधि में रोज के उपयोगकर्ता 86 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसने सबसे कम डिलिवरी दरों में से एक की पेशकश की है। आंकड़े क्विक सर्विस प्लेटफार्मों पर मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की वृद्धि के संबंध में यही कहानी दोहराते हैं।

इस दौरान ब्लिंकइट का मासिक आधार 64 प्रतिशत तक बढ़ गया जो जेप्टो के लिए 93 प्रतिशत अधिक रहा जबकि बीबी नाउ का 18 प्रतिशत बढ़ा।

चीन को छोड़ भारत पर ध्यान दे रहीं वैश्विक खिलौना कंपनियां

शाइन जैकब
चेन्नई, 17 मार्च

खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में चीन के लिए जो बात नुकसान वाली हो सकती है, वह भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। भारत के खिलौना उद्योग ने वित्त वर्ष 15 और वित्त वर्ष 23 के बीच तेजी से प्रगति की है और निर्यात में 239 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई तथा आयात में 52 प्रतिशत तक की गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप देश शुद्ध निर्यातक बन गया।

भारत में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की मंजूरी जरूरी होना, संरक्षणवाद, चीन-प्लस-वन रणनीति और मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत किए जाने से भारत के खिलौना उद्योग में तेजी आई है।

उद्योग के भागीदारों के अनुसार हालांकि हैस्ब्रो, मैटल, स्पिन मास्टर और अर्ली लर्निंग सेंटर जैसे वैश्विक ब्रांड आपूर्ति के लिए देश पर अधिक निर्भर हैं, लेकिन इटली की दिग्गज कंपनी ड्रीम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट और इंकास जैसी प्रमुख विनिर्माता अपना ध्यान धीरे-धीरे चीन से भारत पर केंद्रित कर रहीं हैं।

बीआईएस के नियमन से पहले खिलौनों के लिए भारत की चीन पर 80 प्रतिशत निर्भरता थी, जो अब कम हो गई है।

टायर निर्माता एमआरएफ के स्वामित्व वाली चेन्नई की फंसकूल के मुख्य कार्याधिकारी आर जसवंत ने कहा, 'मैं नहीं मानता कि चीनी क्षमता को बीआईएस द्वारा स्वीकृत किया गया है। आयात पर घरेलू भारतीय उत्पादों का दबदबा है। 10 साल पहले, भारत से मुश्किल से ही किसी तरह की खरीदारी होती थी। आज कई कंपनियों ने भारत में अपना आधार तैयार किया है।' कंपनी हैसब्रो, स्पिन मास्टर, अर्ली लर्निंग सेंटर, फ्लेयर और ड्रूमोंड पार्क गेम्स जैसी अंतरराष्ट्रीय खिलौना कंपनियों को भी आपूर्ति करती है।

कंपनी द्वारा उत्पादित करीब 60 प्रतिशत उत्पाद अब निर्यात बाजारों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका समें जीसीसी, यूरोप के 33 देश शामिल हैं। जसवंत ने कहा कि बीआईएस जैसे सरकारी नीतिगत समर्थन के साथ यह निर्यात जल्द ही 40 से ज्यादा देशों को किया जाएगा। वितरक, आयातक एवं निर्यातक आरपी एसोसिएट्स के मालिक पवन गुप्ता ने कहा, 'भारतीय उत्पादन बढ़ा है और बड़ी तादाद में लोगों ने दिल्ली में अपना आधार बनाया है। चीन से खरीदारी करने वाले कई खरीदार अब अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं तथा भारत इनमें से एक है।

अदाणी समूह करेगा 14 अरब डॉलर का निवेश

अदाणी समूह ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में बंदरगाह, ऊर्जा, हवाई अड्डा, जिंस, सीमेंट और मीडिया क्षेत्र तक फैले अपने कारोबार में 1.2 लाख करोड़ रुपये (लगभग 14 अरब डॉलर) से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है।

सूत्रों ने कहा कि समूह ने अगले 7-10 वर्षों में कारोबार बढ़ाने के लिए अपने निवेश पूर्वानुमान को 100 अरब डॉलर से बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 40 फीसदी अधिक है। विश्लेषकों के अनुसार 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय लगभग 10 अरब डॉलर का पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है। सूत्रों ने कहा कि ये निवेश तेजी से मुनाफे में वृद्धि की बुनियाद तैयार करेंगे। *भाषा*

साकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल बेंगलूरु में खोलेगा दूसरा अस्पताल

जापान की टोयोटा त्सुशो कॉरपोरेशन (टीटीसी) और सेकॉम मेडिकल सिस्टम बेंगलूरु में 1,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से साकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल की भागीदारी में 500 बेड वाला अस्पताल स्थापित करेंगी। करीब 600,000 वर्ग फुट वाला यह नया अस्पताल बनसवाडी में स्थापित किया जाएगा। यहां दो भागीदार पहले से ही साकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल अस्पताल चलाते हैं।

विस्तार योजना के तहत आगामी वर्षों में 1,000 बेड शामिल किए जाएंगे। वर्ष 2026 तक पूरा होने वाले इस नए अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियां और इंडो-जापान आर्कीटेक्चरल डिजाइन शामिल होंगी।

सेकॉम मेडिकल सिस्टम-जापान के अध्यक्ष और सेकाम के कार्यकारी निदेशक तात्सुरो फ्यूसे ने कहा कि हम बेंगलूरु में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सेकॉम मेडिकल सिस्टम और टोयोटा त्सुशो की दक्षता का लाभ उठाने के लिए उत्साहित हैं। *बीएस*

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे मुवक्किल, **मेसर्स मुथूट मनी लिमिटेड (GSTIN 32AABCM5816A1Z4), पंजीकृत कार्यालय: 41/4108, ए-18, बेसमेंट फ्लोर, सरिता थिएटर के सामने, बनर्जी रोड, एर्नाकुलम, केरल – 682018 CIN:U65910KL1994PLC008454, फोन: 0484-2394712, care@muthootgroup.com www.muthootmoney.in** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**31-08-2023** की अवधि तक **कम टंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौती** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

प्रथम नीलामी की तिथि: 26.03.2024

कांकेर खेड़ा-मेरठ (0051): MDL-180

द्वितिय नीलामी की तिथि: 27.03.2024, नीलामी स्थान: मुथूट मनी लिमिटेड, इंडियन बैंक भवन के ऊपर, पहली मंजिल, भगवान सिंह कृषि फार्म, सरधाना रोड, कांकेर खेड़ा-250001

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी **दूसरी नीलामी की तारीख** को क्रमशः **दिये गए नीलामी केंद्र** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: reports@muthootmoney.in

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
केन्द्रीय विपणन संगठन
CENTRAL MARKETING ORGANISATION
Great Place To Work. Certified INDIA

डिमांड रजिस्ट्रेशन नोटिस 2024-2025

सेल वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान एम ओ यू करने के लिए माइल्ड स्टील उत्पादों की अपनी आवश्यकता को दर्शाने के लिए ग्राहकों को आमंत्रित करता है। विस्तृत विवरण **www.sail.co.in** से डाउनलोड किया जा सकता है या सेल के शाखा विक्रय कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।

सेल द्वारा मांग पंजीकरण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 मार्च, 2024 है।

DEMAND REGISTRATION NOTICE 2024-2025

SAIL invites customers to indicate their requirement of mild steel items for consideration of SAIL for entering into MOUs for the financial year 2024-2025. Details can be downloaded from **www.sail.co.in** or obtained from Branch Sales Offices/Regional Offices of SAIL.

Last date for receipt of demand registration applications by SAIL is 27th March, 2024.

Registered Office : Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003
Corporate Identity Number : L27109DL1973GOI006454, Website : www.sail.co.in
There's a little bit of SAIL in everybody's life

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-आक्शन सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-आक्शन से सम्बन्धित सूचना। एडमिन यूनिट/जोन: लखनऊ-पू.उ.रे.-मण्डल-वाणिज्य/पू.उ.रे., नीलामी सूची सं./लॉट सं.: LJN-OOH-04-24, नीलामी सूची प्रकाशन तिथि: 13-03-2024 समय 15:39 बजे, नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट): 01-04-2024 समय 13:00 बजे, नीलामी बन्द करने की तिथि व समय: 01-04-2024 समय 14:20 बजे, नीलामी का प्रकार: Close Ended, वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है: E-Auction Module of *www.ireps.gov.in*

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, लखनऊ
मुजाधि/वाणिज्य–**302**

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
जेम (GeM) निविदा सूचना

सिडबी निम्नलिखित हेतु, पात्र प्रदाताओं को जेम पोर्टल में बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित करता है :

वेबसाइट होस्टिंग सेवाएँ

विस्तृत निविदा दस्तावेज के लिए कृपया Gem Portal (**gem.gov.in**) या हमारी वेबसाइट **www.sidbi.in** देखें। परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, तो उपर्युक्त वेबसाइटों में प्रकाशित किया जाएगा।

बोकारो पावर सप्लाई कं. (प्रा.) लि.
(सेल एवं डीवीसी का एक संयुक्त उपक्रम)
हॉल सं.: एम-01, ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इस्पात भवन, बोकारो स्टील सिटी-827001 (झारखण्ड) CIN: U40300DL2001PTC112074

निविदा आमंत्रण सूचना

संदर्भ सं. : बीपीएससीएल/एमएम/23-24/पेपर एडीवीटी./611 दिनांक: 16/03/2024

क्र	एनआईटी सं./तारीख	विवरण	बीओडी एवं समय
1	बीपीएससीएल/एमएम/23-24/पीयूआर-219/एनआईटी-1424 दिनांक: 06/03/2024	पीटीएफई/पीएफए लाइंड वीयर टाइप डॉयफ्राम वॉल्वों एवं पीएफए लाइंड बॉल वॉल्वों की खरीददारी।	05/04/2024 को 12.15 बजे
2	बीपीएससीएल/एमएम/23-24/पीयूआर-086/एनआईटी-1428 दिनांक: 11/03/2024	मोटरों के साथ विभिन्न सीव ब्लोअरों की खरीददारी।	09/04/2024 को 12.15 बजे
3	बीपीएससीएल/एमएम/23-24/पीयूआर-227/एनआईटी-1432 दिनांक: 15/03/2024	इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल्ट की खरीददारी।	16/04/2024 को 12.15 बजे

निविदा दस्तावेज के लिए कृपया वेबसाइट: www.bpscl.com देखें। बोलीदाताओं से नियमित रूप से हमारी वेबसाइट देखने का अनुरोध किया जाता है।

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अचल संपत्ति हेतु अधिग्रहण सूचना

क्र. सं.	ऋणकर्ता/गारंटर (संपत्ति के स्वामी) का नाम तथा ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधककृत संपत्ति का विवरण (संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश निम्न में समाविष्ट हैं)	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि के अनुसार देय राशि	अधिग्रहण की तिथि एवं प्रकार
1	मन भंवर कंवर एवं प्रकाश सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह, पता: ... खाता संख्या: LAP200006332	[illegible]	मांग सूचना तिथि: 13–04–2021 रु. 4,56,224.41/–	12/03/2024 भौतिक अधिग्रहण

स्थान: राजस्थान, दिनांक: 18–03–2024 (प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

HDFC BANK We understand your world
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा: सी-25, भगवान दास रोड, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 CIN L65920MH1994PLC080618 Website: www.hdfcbank.com पंजीकृत कार्यालय: एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400020

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) में धारा 13(2) सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 (नियम) के नियम 3 के तहत

क्र. सं.	ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री किशन लाल खाता संख्या:617613 15	रू. 11,67,455/- दिनांक 31/01/2024 तक	29-फरवरी -2024	यूनिट नंबर 519, शुभाश्रय होम्स, ग्राम-लोधाना, ... दक्षिण:- यूनिट नंबर 609

* लागू 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से आगे का ब्याज, संभावित खर्चें, लागतें, शुल्क इत्यादी जो भुगतान/वसूली की तिथि तक व्यय किये गये।
यदि उक्त ऋणी एचडीएफसी लिमिटेड को कथित भुगतान करने में असमर्थ रहते है तब एचडीएफसी लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों का पूर्णरूप से कथित ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों की जोखिम पर लागतों तथा परिणामों हेतु उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। ऋणी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कथित प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों में विक्रय, पट्टे या अन्य किसी तरीके से बिना एचडीएफसी लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के स्थानान्तरण करने हेतु निषिद्ध है कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों या बनाये गये नियमों का उल्लंघन या विरोध करता है तो वह अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अर्थदण्ड/सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक:- 17.03.2024 स्थान:- रेवाड़ी (हरियाणा) हस्ताक्षर, प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

समक्ष राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण
इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज
(मूल न्यायक्षेत्र)
कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए)– 01(एएलडी) वर्ष 2024
कंपनी अधिनियम, 2013 (18 वर्ष 2013) की धाराएँ 230 और 232 के मामले में
और
प्रबंधन योजना के मामले में
और
इनके मामले में
अंबा पैनल इंडिया प्रा. लि. ...आवेदक नं. 1/डिमर्ज्ड कंपनी
और
अंबा लैमीनेट प्रा. लि. ...आवेदक नं. 2/परिणामी कंपनी

पृथक बैठक आयोजन नोटिस

अंबा पैनल इंडिया प्रा. लि.	समय
प्रत्याभूत लेनदार	दोपहर 12:30
अप्रत्याभूत लेनदार	अप. 03:30
अंबा लैमीनेट प्रा. लि.	**समय**
प्रत्याभूत लेनदार	अप. 01:30
अप्रत्याभूत लेनदार	अप. 04:30

श्री ब्रज भूषण गुप्ता	97170 98710, amba294@gmail.com
सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.	1800 22 55 33 (निःशुल्क) helpdesk.evoting@cdslindia.com

विवरण	वेबसाइट
अंबा लैमीनेट प्रा. लि.	www.ogaanlam.com

रिमोट ई–मतदान की शुरुआत	सोमवार, 15 अप्रैल, 2024 समय पूर्वा. 9:00 भा.मा.स.
रिमोट ई–मतदान की समाप्ति	गुरुवार, 18 अप्रैल, 2024 समय अप. 5:00 भा.मा.स.

दिनांकित 11 मार्च, 2024

हस्ता./– राहुल चौधरी, एडवोकेट, बैठकों के सर्वनिष्ठ अध्यक्ष

माध्यम से, हस्ता./– कार्तिकेय गोयल, एडवोकेट, हिते राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स, आवेदकों के लिए अधिवक्ता, 785, पॉकेट–ई, मयूर विहार–II, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे/एनएच–24, दिल्ली–110091, ई–मेल: rajeev391@gmail.com, वेबसाइट: www.rgalegal.in

प्रपत्र सं. आईएनसी–25"ए"
पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के विषय में

तथा

मैसर्स फरक्का–रायगंज हाईवेज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–376, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, दिल्ली – 110092 में स्थित है, के विषय में

.........**आवेदक**

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी इसको पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में 15 मार्च, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित उपरोक्त नियमों के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छुक है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :

फरक्का–रायगंज हाईवेज लिमिटेड
बी–376, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, दिल्ली – 110092, भारत

कृते एवं हिते आवेदक
फरक्का–रायगंज हाईवेज लिमिटेड
हस्ता./–
दीपन हेमंत कुमार शाह
निदेशक
तिथि : 16/03/2024 **डीआईएन : 09783231**
स्थान : नई दिल्ली

PUBLIC NOTICE
To whomsoever it may concern

This is to inform the General Public that the following share Certificates of Chambal Fartilisers and Chemical Limited ("The Company") having its Registered Office at Gadepan, District Kota Rajasthan - 325 208, has/have been lost by the shareholder(s)

Name(s) of Registered Shareholders	Certificate Nos.	Folio No.	No. of Shares
1. Om Prakash Khatri 2. Surila	775910 - 775919	E0107892	1000
1. Om Prakash Khatri 2. Surila	775920 - 775929	E0107893	1000
1. Om Prakash Khatri 2. Surila	775960 - 775969	E0107897	1000
1. Surila 2. Om Prakash Khatri	775930 - 775939	E0107894	1000
1. Surila 2. Om Prakash Khatri	775950 - 775959	E0107896	1000
1. Surila 2. Om Prakash Khatri	775970 - 775979	E0107898	1000

In pursuance of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund)Rules, 2016 the aforesaid shares have been transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority"). I am claiming the aforesaid shares from IEPF Authority and requesting the Company to issue entitlement letter for the above - mentioned shares. The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above - mentioned share certificate(s)

Any person who has any objection/claim in respect of the aforesaid share certificate(s) should lodge the objection/claim with the Company or its Share Transfer Agent-Zuari Finserv Limited, Plot No.2, Zamrudpur Community Centre, kailash Colony Extention, New Delhi - 110025 within a period of 30 days of publication of this notice after which no claim will be entertained. The Company may thereafter issue entitlement letter against the aforesaid share certificate(s), upon submission of all requisite documents to the satisfaction of the Company, for claiming the share from IEPF Authority

Name(s) of Shareholder(s)/Legal Heir(s)
Place : Rajsthan (Kota) **OM PRAKASH KHATRI**
Date : 18/03/2024 **SURILA DEVI KHATRI**

दिल्ली संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ.प्र. से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नईदिल्ली से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल आरएनआई नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

सन फार्मा का स्पेशियलिटी पोर्टफोलियो मजबूत

ब्रोकरों ने भरोसा दिखाते हुए 2024-25 के लिए ईपीएस अनुमान और कीमत लक्ष्य बढ़ाए हैं। यह शेयर वित्त वर्ष 2024 में चढ़ने वाले प्रमुख दवा शेयरों में से एक रहा है और करीब 57 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज करने में कामयाब रहा

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 17 मार्च

अपने स्पेशियलिटी पोर्टफोलियो में तेजी, घरेलू बाजार में बढ़ता प्रदर्शन और बेहतर नियामकीय अनुपालन देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के लिए सकारात्मक बदलाव हैं।

इन सकारात्मक कारकों को देखते हुए कुछ ब्रोकरों ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने प्रति शेयर आय (ईपीएस) और कीमत लक्ष्य के अनुमान बढ़ा दिए हैं। इससे शेयर के लिए मजबूती बरकरार रहनी चाहिए। यह शेयर वित्त वर्ष 2024 में चढ़ने वाले प्रमुख दवा शेयरों में से एक रहा है और करीब 57 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज करने में कामयाब रहा। यह शेयर इस समय 1,547 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

हालंकि इसके स्पेशियल्टी सेगमेंट के लिए आधार ऊंचा है लेकिन ब्रोकरों का मानना है कि कंपनी वृद्धि की मजबूत दर बरकरार रखेगी। शेयरखान रिसर्च के अनुसार सन के अमेरिकी प्रिस्क्रिप्शन आंकड़े से स्पेशियल्टी पोर्टफोलियो में मजबूत तेजी का पता चलता है। सन का स्पेशियल्टी पोर्टफोलियोसेक्युआ (ड्राई आई), इलुम्या (सोरायसिस), विनलेवी (एक्ने) और लेवुलान (कैंसर) की बिक्री में मजबूत वृद्धि से बढ़ा है।

ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि सन का स्पेशियल्टी व्यवसाय वित्त वर्ष 2026 तक 17 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़कर 1.4 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। फरवरी के निर्यात आंकड़ों से सन के लिए मजबूत सुधार का संकेत मिला है। कंपनी को कैंसर दवा रेवलिमिड से मदद मिली। रेवलिमिड की सकल बिक्री 14 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। इसमें तेजी संभावित थी, क्योंकि इस दवा से योगदान दिसंबर तिमाही में सीमित रहा। दिसंबर तिमाही में इसका मजबूत प्रदर्शन उसकी सहायक इकाई टारो के बेहतर मार्जिन और इलुम्या भागीदारी से 2 करोड़ डॉलर की मदद से बढ़ा।

अब इसका टारो पर पूरा नियंत्रण है, इस वजह से समेकित इकाई को विनिर्माण क्षेत्रों में लागत तालमेल और एकीकरण से लाभ मिलना चाहिए। सन अपने अधिग्रहणों के वित्तपोषण के लिए टारो की नकदी का उपयोग कर सकती है। अनुपालन में सुधार अन्य सकारात्मक बदलाव है। ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि गुजरात के अंकलेश्वर में सन की ऐक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट इकाई को नो एक्शन इंडेकेटड दर्जा मिला है, जिससे उसके लिए उत्पादों का विनिर्माण एवं निर्यात करने की राह आसान हो गई है।

हालांकि यह सकारात्मक है, लेकिन इलारा सिक्योरिटीज में विश्लेषक बीनो पतीपरम्पिल का मानना है कि हलोल और मोहाली संयंत्रों पर अमेरिकी दवा नियामक की कार्रवाई के लंबे असर ने डेरुक्सोलिटिनिब की अमेरिकी पेशकश में विलंब बढ़ा दिया जो उसके अनुमानों के लिए अन्य जोखिम है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के बाद ब्रोकरेज फर्म ने न सिर्फ वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने आय अनुमान 3-5 प्रतिशत तक बढ़ाए हैं बल्कि उसने इस शेयर के लिए कीमत लक्ष्य भी बढ़ाकर 1,524 रुपये कर दिया है। भारतीय व्यवसाय के लिए कंपनी ने प्रिस्क्रिप्शन-केंद्रित वृद्धि पर ध्यान दिया है।

लगातार पांच तिमाहियों तक सुस्त प्रदर्शन के बाद वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में वृद्धि की रफ्तार तेज हुई और तीसरी तिमाही में भी यह बनी रही। इन दोनों तिमाहियों में 11-11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जहां कुछ ब्रोकरों का मानना है कि कंपनी मजबूत एक अंक में वृद्धि दर्ज करेगी वहीं अन्य का कहना है कि यह या तो भविष्य में फार्मा बाजार की वृद्धि के अनुरूप या उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी। बिक्री और नई पेशकशों का सन के भारतीय व्यवसाय में तीन-चौथाई योगदान है जबकि पूरे दवा बाजार के लिहाज से यह दो-तिहाई है।

चिकित्सा प्रतिनिधि बल की संख्या 20 प्रतिशत तक बढ़ने से कंपनी को छोटे और मझोले बाजारों में अपनी पैठ बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आईआईएफएल रिसर्च के शोध विश्लेषकों राहुल जीवानी और नमन बगरेचा का मानना है कि कंपनी स्पेशियल्टी व्यवसाय में लगातार तेजी, अमेरिकी जेनेरिक्स पर घटती निर्भरता और भारतीय व्यवसाय में दो अंक की वृद्धि की मदद से आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। ब्रोकरेज फर्म ने 1,625 रुपये कीमत लक्ष्य के साथ इस शेयर को खरीदें रेटिंग दी है।

घरेलू दवा बाजार में मजबूत स्थिति को ध्यान में रखते हुए शेयरखान रिसर्च ने भी सन फार्मा के शेयर को 'खरीदें' रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने आय अनुमान 1 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। उन्होंने शेयर की कीमत का लक्ष्य भी बढ़ाकर 1,727 रुपये कर दिया है।

मार्जिन में सुधार

	2023-23	2024-25ई	2025-26ई
शुद्ध बिक्री (करोड़ रु.)	47,420	52,578	61,077
सालाना बदलाव %	9.6	10.9	16.2
परिचालन लाभ मार्जिन %	27.5	28.6	29.7
शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)	9,418	11,503	13,823
सालाना बदलाव %	10.0	22.1	20.2
पीई अनुपात) (गुना)	38.3	32.9	26.9

ई: अनुमानित | स्रोत: शेयरखान रिसर्च

सवाल जवाब

गिरावट से स्मॉलकैप में बुलबुले की समस्या दूर हुई है

आदित्य बिड़ला सन लाइफ ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) में सह-मुख्य निवेश अधिकारी एवं इक्विटी प्रमुख हरीश कृष्णन ने अभिषेक कुमार के साथ साक्षात्कार में कहा कि जहां लार्जकैप क्षेत्र में रिस्क-रिवार्ड अनुकूल बना हुआ है, वहीं ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाले और स्मॉलकैप पर दांव लगाने वाले निवेशक उन कंपनियों पर विचार कर सकते हैं जिनके शेयर भाव नीचे आए हैं। कृष्णन का कहना है कि एएमसी घरेलू-केंद्रित व्यवसायों पर उत्साहित बनी हुई हैं। उनसे बातचीत के मुख्य अंश:

क्या स्मॉलकैप शेयरों में ताजा गिरावट से मूल्यांकन उचित हो गया है? स्मॉलकैप में कौन से क्षेत्र अब ज्यादा आकर्षक हो गए हैं?

स्मॉलकैप सूचकांकों में अपने ऊंचे स्तर से करीब 12 प्रतिशत तक गिरावट आई है और अब वे दिसंबर 2023 के स्तर तक पर वापस आ गए हैं। इस गिरावट से कुछ हद तक बाजार में झाग की स्थिति दूर हुई है,लेकिन सूचकांक अभी भी पिछले साल से 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़े हुए हैं। हालांकि ऐसे कई शेयर हैं जिनमें सूचकांक के मुकाबले बड़ी गिरावट आई है। स्मॉलकैप निवेश 'बॉटम-अप' दांव ज्यादा है, इसलिए सेक्टोरल स्तर पर स्पष्ट कह पाना चुनौतीपूर्ण है। हम रसायन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोटिव एंसिलियरीज, पूंजीगत वस्तु और वित्त जैसे क्षेत्रों में ज्यादा अवसर देख रहे हैं।

क्या कम स्मॉलकैप शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए अपना निवेश बढ़ाने का यह सही समय है?

निवेशकों को अपने परिसंपत्ति आवंटन पर ध्यान देना चाहिए। हम निवेशकों को इक्विटी पर तटस्थ नजरिया और लार्जकैप पर ओवरवेट रहने का सुझाव दे रहे हैं। मौजूदा गिरावट जैसे हालात ने निवेशकों को अपना परिसंपत्ति आवंटन संतुलित बनाने का मौका दिया है। यदि रिस्क प्रोफाइल अनुमति दे तो निवेशकों को अपना निवेश उन शएयरों में बढ़ाने पर विचार करना चाहिए जिनमें उनका निवेश कम है।

क्या आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड घरेलू-आधारित व्यवसायों पर अभी भी उत्साहित है, जैसा कि वह साल के शुरू में था? कौन से क्षेत्र प्रतिफल के लिहाज से बेहतर हैं?

हम घरेलू चक्रीयता पर सकारात्मक नजरिया बनाए हुए हैं। वाहन, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जैसे क्षेत्र और विनिर्माण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर जेसी निवेश थीमों से जिनको फा.दा होगा, उनको लेकर हम दीर्घावधि के लिहाज से सकारात्मक हैं। बुनियादी आधार के अलावा हम व्यापार चक्र के नजरिए से भी क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं। संकेत यही हैं कि वाहन, पूंजीगत वस्तु, रियल एस्टेट, सीमेंट और आईटी जैसे क्षेत्रों ने मध्यावधि में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पिछले 18-24 महीनों के दौरान ये पहले ही अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। दूसरी तरफ फार्मास्युटिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, धातु और मीडिया जैसे क्षेत्रों में बदलाव देखा जा सकता है।

निर्यात-केंद्रित व्यवसायों पर आपका क्या नजरिया है?

हमारा मानना है कि भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ रही है। वैश्विक मंदी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंका को लेकर अल्पावधि चिंताएं हैं और है। इसे देखते हुए हम आईटी सेवाओं, ऑटोमोटिव, पूंजीगत वस्तु, फार्मास्युटिकल या रसायन जैसे वैश्विक बाजारों से जुड़ी कंपनियों में निवेश बढ़ाने की संभावना देख रहे हैं।

अर्थव्यवस्था पर आपका नजरिया क्या है? क्या वृद्धि से ऊंचे मूल्यांकन को मदद मिल सकेगी?

कुछ दशक पहले तक भारतीय कंपनियों में रुचि रखने वाले वैश्विक निवेशकों के लिए वृहद आर्थिक कमजोरियां चिंता का प्रमुख विषय थीं जो उनके वास्तविक मूल्यांकन को प्रभावित कर रही थीं। लेकिन हाल के समय में हालात काफी बदले हैं। अब हमने वित्तीय और मौद्रिक नीति दोनों के लिए काउंटर-सिक्लीकल दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि वृद्धि अनुकूल बनी हुई है। हालांकि वैश्विक घटनाक्रम भारतीय बाजार के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे काउंटर-सिक्लीकल दृष्टिकोण का मतलब है कि हमारे पास वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त विकल्प हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मूल्यांकन बढ़ा हुआ है।

बाजार हलचल

शेयर बाजारों पर अब नकदी संकट की बाधा

स्मॉल और मिडकैप के खिलाफ नियामकीय कार्रवाई के अलावा इस महीने शेयरों को नकदी के तंग हालात का सामना करना पड़ रहा है। बाजार पर नजर रखने वालों ने कहा कि अग्रिम कर के तौर पर नकदी की निकासी और पूंजीगत लाभ से संबंधित समायोजन अल्पावधि में बाजारों पर असर डालेंगे। अगर किसी कारोबारी पर पूंजीगत लाभ के तौर पर 10,000 रुपये से ज्यादा की देनदारी है तो उसे इस महीने अग्रिम कर चुकाना होगा। इसके अलावा घाटे में शेयर बेचकर पूंजीगत लाभ से नुकसान की भरपाई की जा सकती है। एक विश्लेषक ने कहा कि अगले महीने कुछ बिकवाली हो सकती है क्योंकि कुछ कारोबारी मुनाफावसूली के लिए अगले वित्त वर्ष का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह पूंजीगत लाभ पर कर भुगतान को अभी टाल सके। एनएसई का निफ्टी-50 आखिरी बार 22,023 पर बंद हुआ था। विश्लेषकों ने कहा कि अगर इंडेक्स गिरावट में 21,800 का स्तर तोड़ता है तो इसमें तीन फीसदी की और गिरावट आ सकती है।

स्ट्रेस टेस्ट से फंड मैनेजरों की रणनीति का हुआ खुलासा

शेयरों की बिक्री पर लगने वाले दिनों के अलावा स्ट्रेस टेस्ट के आंकड़ों ने एक अन्य अहम पहलू को सुर्खियों में ला दिया है। नतीजे बताते हैं कि स्मॉल व मिडकैप फंड मैनेजरों के निवेश के स्टाइल काफी ज्यादा अलग-अलग हैं। मिडकैप फंडों के लिए पीई अनुपात 21 गुना से लेकर 62 गुना तक है। स्मॉलकैप श्रेणी में पीई अनुपात 18.6 गुना से लेकर 48 गुना तक है। उद्योग पर नजर रखने वालों ने कहा कि नतीजे बताते हैं कि कुछ फंड मैनेजर ग्रोथ वाले शेयरों के लिए कोई भी रकम चुकाने के इच्छुक होते हैं और वे मूल्यांकन को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होते। दूसरी ओर महंगे मूल्यांकन की चिंता के कारण कुछ उन शेयरों की शरण लेना चाहते हैं जहां मूल्यांकन अभी भी निवेश लायक है।

कमजोर लिस्टिंग से निवेशकों की उम्मीद पर चोट

पिछले हफ्ते तीन आरंभिक सार्वजनिक निर्गम अपने शुरुआती कारोबार के दौरान धराशायी हो गए। अत्यधिक बुलबुले को लेकर चिंता से स्मॉलकैप में बिकवाली के बीच गोपाल स्नैक्स, जेजी केमिकल्स और आरके स्वामी के शेयरों में पहले दिन 8.6 फीसदी से 16.5 फीसदी के बीच गिरावट आई। आईपीओ को निवेशकों से मिले अच्छे समर्थन के बावजूद सूचीबद्धता के दिन इनकी लिस्टिंग कमजोर हुई। एक निवेश बैंकर ने कहा कि आईपीओ बाजार के लिए सेंटिमेंट में काफी तेजी से बदलाव हो सकता है। पिछले हफ्ते के कमजोर प्रदर्शन ने निवेशकों की उम्मीदें धूमिल कर दीं। अब वास्तविकता यह है कि सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाले इश्यू ही बाजारों में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि आईपीओ गतिविधियां अभी से लेकर चुनाव के नतीजों तक सुस्त पड़ जाएगी लेकिन द्वितीयक बाजार में अच्छी कंपनियां अपनी रफ्तार बनाए रखेंगी।

संकलन : अभिषेक कुमार और सुंदर सेतुरामन

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 5 फर्मों का एमकैप घटा

सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से पांच के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह सामूहिक रूप से 2,23,660 करोड़ रुपये की गिरावट आई। शेयर बाजार में कमजोरी के रुख के बीच सबसे अधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को उठाना पड़ा। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,475.96 अंक या 1.99 फीसदी नीचे आया। सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और आईटीसी की बाजार हैसियत बढ़ गई। समीक्षाधीन सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 81,763.35 करोड़ रुपये घटकर 19,19,595.15 करोड़ रुपये पर आ गया। सबसे अधिक नुकसान में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही।

भाषा

फंडों ने पेटीएम की एक-चौथाई हिस्सेदारी बेची

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद से म्युचुअल फंडों (एमएफ) ने वन97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम) में अपनी एक-चौथाई हिस्सेदारी घटाई है। नुवामा अल्टरनेटिव ऐंड क्वांटीटेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट से पता चला है कि फरवरी के अंत में म्युचुअल फंडों के पास पेटीएम के 3.28 करोड़ शेयर थे, जो जनवरी के अंत (4.45 करोड़) की तुलना में 26 प्रतिशत कम हैं।

कुल हिस्सेदारी (जिसमें पैसिव फडों का निवेश भी शामिल है) का मूल्य मौजूदा भाव पर 1,212 करोड़ रुपये है। पेटीएम का शेयर भाव आरबीआई की सख्ती की वजह से फरवरी में गिरकर लगभग आधा रह गया। 31 जनवरी को बैंकिंग नियामक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर गैर-अनुपालन और निगरानी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगा दिए थे।

म्युचुअल फंडों ने ज़ी एंटरटेनमेंट में भी अपना निवेश घटाया है। इस शेयर को भी नियामकीय समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस शेयर में म्युचुअल फंडों का निवेश 71 लाख शेयर तक घट गया। सुंदरम एमएफ और फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ पूरी तरह इस शेयर से बाहर हो गए। खरीदारी की बात की जाए तो पता चलता है कि एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगातार दूसरे महीने सबसे ज्यादा एमएफ निवेश आकर्षित किया। फंडों ने जनवरी-फरवरी की अवधि के दौरान एचडीएफसी बैंक में 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया। वहीं इससे पहले के दो महीनों में म्युचुअल फंड इस बैंकिंग दिग्गज में शुद्ध बिकवाल रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस के शेयर में निवेश पिछले महीने बढकर 3,760 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सर्वाधिक खरीदे और बेचे गए शेयरों की सूची समग्र आधार पर बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है। जहां एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ऐक्सिस बैंक शीर्ष-20 खरीदारी वाले शेयरों की सूची में रहे, वहीं पंजाब नैशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बंधन बैंक और केनरा बैंक सर्वाधिक बेचे गए 20-शीर्ष शेयरों में शामिल रहे।

- अभिषेक कुमार

एचडीएफसी बैंक, आरआईएल में एमएफ की दिलचस्पी

सबसे ज्यादा खरीदे गए शेयर

	निवेश में बढ़ोतरी (करोड़ रुपये में)
एचडीएफसी बैंक	8,280
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,760
व्हर्लपूल	3,070
एलऐंडटी	2,510
कोटक महिंद्रा बैंक	2,370
कल्याण ज्वैलर्स	1,940
आईओसीएल	1,450

सबसे ज्यादा बिकने वाले शेयर

	निवेश में गिरावट (करोड़ रुपये में)
सन फार्मा	2,290
महिंद्रा ऐंड महिंद्रा	1,690
एनटीपीसी	1,680
एनएमडीसी	1,490
इंटरग्लोब एविएशन	1,320
पंजाब नैशनल बैंक	1,300
एनएचपीसी	1,270

स्रोत: नुवामा अल्टरनेटिव ऐंड क्वांटीटेटिव रिसर्च

मार्च के पहले पखवाड़े में एफपीआई का निवेश 40,710 करोड़ रुपये

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने (मार्च में) के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों में 40,710 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। वृहद आर्थिक परिदृश्य में सुधार और घरेलू मोर्चे पर मजबूत आंकड़ों से एफपीआई का भारतीय शेयरों में आकर्षण बना हुआ है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले फरवरी में एफपीआई ने शेयरों में 1,539 करोड़ रुपये का निवेश किया था। वहीं जनवरी में उन्होंने 25,743 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि एफपीआई अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल में बदलाव की वजह से अपनी रणनीति बदल रहे हैं। चूंकि अमेरिका में बॉन्ड पर प्रतिफल फिर बढ़ गया है, ऐसे में आगामी दिनों में एफपीआई फिर बिकवाली कर सकते हैं।

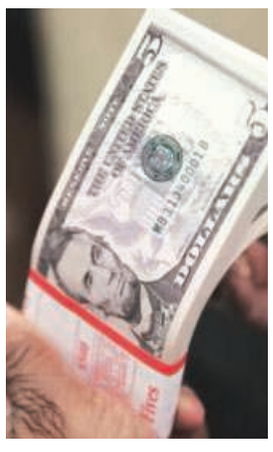

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के सहायक निदेशक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, 'वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार की वजह से एफपीआई भारत जैसे बाजारों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा बाजार में हालिया 'करेक्शन' से भी उन्हें निवेश का अवसर मिला है। शेयरों के अलावा एफपीआई ने समीक्षाधीन अवधि में ऋण या बॉन्ड बाजार में 10,383 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ऋण या बॉन्ड बाजार की बात की जाए, तो ब्लूमबर्ग ने अगले साल 31 जनवरी से भारतीय बॉन्ड को इमर्जिंग मार्केट (ईएम) लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा की है। इसके चलते एफपीआई बॉन्ड बाजार में पैसा लगा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बॉन्ड बाजार में फरवरी में 22,419 करोड़ रुपये, जनवरी में 19,836 करोड़ रुपये, दिसंबर में 18,302 करोड़ रुपये का निवेश किया था। कुल मिलाकर इस साल अबतक एफपीआई भारतीय शेयर बाजार में 16,505 करोड़ रुपये डाल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ऋण बाजार में 52,639 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

भाषा

कजारिया सिरैमिक्स के लिए निकट अवधि में मांग की चिंता कायम

प्रबंधन और ब्रोकरेज फर्मों ने वित्त वर्ष 2025 में जोरदार सुधार का अनुमान जताया है

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 17 मार्च

देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध सिरैमिक टाइल निर्माता कजारिया सिरैमिक्स का दिसंबर तिमाही का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इस तिमाही में कमजोर घरेलू मांग से बिक्री पर असर पड़ा जबकि प्राप्तियों में कमी के कारण राजस्व भी औसत से कम रहा। निराशा भरी तीसरी तिमाही और वित्त वर्ष 24 की शेष अवधि के दौरान निकट भविष्य की मांग संबंधी चिंताओं के कारण यह शेयर इस महीने अपने शीर्ष स्तर से नौ प्रतिशत गिर चुका है। कंपनी की 2.7 करोड़ वर्ग मीटर की कुल मात्रात्मक बिक्री पिछले साल की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक रही जबकि प्राप्तियां तीन प्रतिशत तक गिरकर 374 रुपये प्रति वर्ग मीटर रह गईं।

मांग में नरमी का यह रुख लगातार जारी है क्योंकि दिसंबर में समाप्त नौ महीने में वॉल्यूम और बिक्री क्रमशः सात प्रतिशत और चार प्रतिशत के साथ निचले स्तर पर बनी हुई है। चौथी तिमाही का वॉल्यूम इस साल अब तक के प्रदर्शन को बता सकता है और इस प्रकार यह छह से सात प्रतिशत वृद्धि के साथ समाप्त होगी। तिमाही के दौरान इस क्षेत्र और कंपनी के लिए सकारात्मक बात यह रही कि इनपुट लागत कम थी। ऊर्जा की कम होती लागत से कंपनी को परिचालन लाभ में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने में सहायता मिली जबकि परिचालन लाभ मार्जिन पिछले साल की तुलना में 330 आधार अंक बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गया।

बिक्री प्रतिशत के रूप में ईंधन का खर्च 20.8 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले की तिमाही के 25.5 प्रतिशत की तुलना में 570 आधार अंक कम रहा। अलबत्ता तिमाही आधार पर यह 50 आधार अंक ऊपर है। अधिक वॉल्यूम के साथ-साथ बिजली और ईंधन की लागत में कमी कंपनी के लिए फायदेमंद है। उम्मीद है कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए छूट और प्रोत्साहन के जरिये बचत का कुछ हिस्सा डीलरों के साथ साझा किया जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 24 में मार्जिन 14 से 16 प्रतिशत और वित्त वर्ष 25 में 15 से 17 प्रतिशत के बीच रहेगा।

हालांकि मार्च तिमाही और वित्त वर्ष 24 में वॉल्यूम का रुख कम रहने के आसार हैं लेकिन वित्त वर्ष 25 में प्रबंधन और ब्रोकरेज की टिप्पणी में दमदार सुधार का अनुमान जताया गया है। कंपनी को आगे चलकर इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और वह उद्योग के औसत के मुकाबले 500 से 600 आधार अंक अधिक वृद्धि की उम्मीद कर रही है।

चिंता के साथ उम्मीद भी

- **निराशा भरी तीसरी तिमाही और वित्त वर्ष 24 की शेष अवधि के दौरान निकट भविष्य की मांग संबंधी चिंताओं के कारण यह शेयर इस महीने अपने शीर्ष स्तर से नौ प्रतिशत गिर चुका है**
- **कंपनी को आगे चलकर इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और वह उद्योग के औसत के मुकाबले 500 से 600 आधार अंक अधिक वृद्धि की उम्मीद कर रही है।**

संक्षेप में

खाताधारकों के हितों की रक्षा करें बैंक : जोशी

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने और खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियां ग्राहकों से पॉलिसी खरीदने के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपना रही हैं। ऐसे उदाहरण हैं, जहां दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में 75 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों को जीवन बीमा पॉलिसी बेची गईं। आमतौर पर, बैंक असहायक बीमा कंपनियों के उत्पादों को बेचने की कोशिश करते हैं। अगर ग्राहक इसका विरोध करते हैं, तो शाखा अधिकारी कहते हैं कि उन पर ऊपर से दबाव है। *भाषा*

खान के समीप तापीय परियोजनाएं बनाएं

कोयला मंत्रालय ने परिवहन लागत को कम करने और शुष्क ईंधन की उपलब्धता में सुधार के उद्देश्य से कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को कोयला खानों के पास (पिटहेड) तापीय परियोजनाएं शुरू करने के लिए कहा है। कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि योजना यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड की सभी नई तापीय परियोजनाएं कोयला खदानों के पास होनी चाहिए। कोल इंडिया उत्तर प्रदेश और बिहार में तापीय परियोजनाओं की संभावनाएं तलाश रही है। *भाषा*

स्विस कंपनियां भारत में निवेश की इच्छुक

चॉकलेट बनाने वाली कंपनी बैरी कैलेबाउट समूह और प्रौद्योगिकी कंपनी बुहलर सहित स्विट्जरलैंड की कई कंपनियां भारत में निवेश करने की इच्छुक हैं। स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की मंत्री हेलेन बडलिगर ने कहा कि एचईएसएस ग्रीन मोबिलिटी का इरादा 2025 तक भारत में लगभग 3,000 इलेक्ट्रिक बसों का विनिर्माण करने का है। उन्होंने ईमेल से दिए साक्षात्कार में बताया कि चॉकलेट निर्माता बैरी कैलेबाउट ग्रुप 2024 तक भारत में अपनी तीसरी विनिर्माण इकाई चालू करने के लिए तैयार है। कई कंपनियां निवेश की इच्छुक हैं। भारत और चार देशों के यूरोपीय समूह ईएफटीए ने 10 मार्च को व्यापार समझौते - व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे। इन देशों में आइसलैंड, लीशटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। *भाषा*

देश में मिट्टी के तेल की खपत 26 प्रतिशत घटी

देश में केरोसिन या मिट्टी के तेल की खपत में 2013-14 और 2022-23 के बीच साल-दर-साल आधार पर 26 की भारी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण सरकार की स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की नीतियां हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों 'ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2024' में कहा गया है, 'हाल के समय की ऊर्जा नीतियों का प्रभाव देश में ईंधन के रूप में केरोसिन की खपत पर स्पष्ट दिखता है।' *भाषा*

आंध्र प्रदेश और केरल में सबसे महंगा है पेट्रोल

देश में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पूर्वोत्तर जैसे छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वाहन ईंधन के दाम सबसे कम हैं। स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर की दरों में अंतर की वजह से वाहन ईंधन कीमतों में भिन्नता है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल सबसे महंगा 109.87 रुपये प्रति लीटर है। इसके बाद केरल में एक लीटर पेट्रोल 107.54 रुपये में बिक रहा है। तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत 107.39 रुपये प्रति लीटर है। भोपाल में पेट्रोल 106.45 रुपये, पटना में 105.16 रुपये, जयपुर में 104.86 रुपये और मुंबई में 104.19 रुपये है। अंडमान और निकोबार द्वीप में पेट्रोल सबसे सस्ता है जहां यह 82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। *भाषा*

निर्यात 20 माह की ऊंचाई पर

असित रंजन मिश्र
नई दिल्ली, 17 मार्च

भारत का निर्यात फरवरी में 20 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

प्रमुख निर्यात गंतव्यों जैसे अमेरिका, यूएई, सिंगापुर व दक्षिण अफ्रीका को निर्यात बढ़ने के कारण निर्यात में दो अंकों की वृद्धि हुई।

वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बीते वर्ष दिसंबर से लगातार तीन महीनों तक निर्यात में इजाफा हुआ। हालांकि वर्ष 2023 की ज्यादातर अवधि में वस्तु निर्यात वृद्धि ऋणात्मक दायरे में थी। फिच रेटिंग्स ने बीते सप्ताह वैश्विक वृद्धि के अनुमान को 30 आधार अंक बढ़ाकर 2.4 फीसदी कर दिया है। अल्पावधि में विश्व में वृद्धि के बेहतर रुझान का अनुमान जताया गया है। अमेरिका में वृद्धि के अनुमान को इस कैलेंडर वर्ष में बढ़ाकर 2.1 फीसदी कर दिया गया है जबकि यह पहले 1.2 फीसदी अनुमानित था।

फिच रेटिंग्स ने कहा, 'वर्ष 2023 में अमेरिकी राजकोषीय घाटे में अभूतपूर्व चक्रीय वृद्धि ने घरेलू मांग को बढ़ावा दिया और जीडीपी वृद्धि को मजूबत ढंग से आगे बढ़ने में मदद की। हालांकि अनुमान यह है कि राजकोषीय प्रभाव इस वर्ष कम हो सकता है और घरेलू आमदनी में वृद्धि कम होगी। वास्तविक रूप में ब्याज दरों की वृद्धि के कारण बीते वर्ष सख्त मौद्रिक नीति का प्रभाव इस वर्ष कम हो रहा है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि तिमाही दर तिमाही वृद्धि इस वर्ष के अंत तक वृद्धि पर्याप्त कम हो जाएगी।'

भारत के लिए निर्यात का सबसे शीर्ष गंतव्य अमेरिका रहा। भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात फरवरी में 22 फीसदी बढ़कर 7.2 अरब डॉलर हो गया। जनवरी में अमेरिका को सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाला उत्पाद स्मार्टफोन (53 करोड़ डॉलर) हो गया और इसने पहले स्थान पर रहने वाले पॉलिश्ड हीरे (38 करोड़ डॉलर) का स्थान ले लिया है।

इससे अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान भारत से स्मार्टफोन के निर्यात का शीर्ष गंतव्य यूएई की जगह अमेरिका हो गया। इस अवधि में अमेरिका को कुल 4.1 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ जबकि यूएई को 2.2 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ। स्मार्टफोन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात फरवरी में 54.8 फीसदी बढ़ गया और इसमें लगातार वृद्धि नजर आ रही है।

फरवरी में यूएई को भेजे जाने वाली निर्यात की खेप 23.1 फीसदी बढ़कर 3.5 अरब डॉलर हो गई और यह दूसरे नंबर पर निर्यात का गंतव्य रहा। यूएई को होने वाले निर्यात में गैरजड़ित सोना (31.7 करोड़ डॉलर), स्मार्टफोन (23.7 करोड़ डॉलर) और वाहन के ईंधन (24.3 करोड़ डॉलर) की प्रमुख हिस्सेदारी थी।फरवरी में सिंगापुर को होने वाला निर्यात 51.6 फीसदी बढ़कर 1.85 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल – फरवरी की अवधि में भारत के निर्यात का पांचवां सबसे बड़ा गंतव्य सिंगापुर बना हुआ था जबकि यह फरवरी में सुधरकर चौथे स्थान पर आ गया था।

आधार कम होने के कारण दक्षिण अफ्रीका का निर्यात दोगुना हो गया। दक्षिण अफ्रीका को 1.16 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। अप्रैल-फरवरी की समन्वित अवधि में भारत के निर्यात गंतव्यों में दक्षिण अफ्रीका का स्थान उछलकर 10वां हो गया जबकि बीते साल की इसी अवधि में यह 16वें स्थान पर था। भारत से दक्षिण अफ्रीका को सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों का हुआ। पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का कम निर्यात हुआ था लेकिन अक्टूबर के बाद पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में निरंतर वृद्धि जारी है। भारत से दक्षिण अफ्रीका को होने वाले ऐसे उत्पादों का निर्यात 89 फीसदी बढ़कर 21.9 करोड़ डॉलर हो गया। फरवरी में शीर्ष के अन्य निर्यात गंतव्यों में सऊदी अरब (50 फीसदी), नीदरलैंड (26.7 फीसदी), ब्रिटेन (31.9 फीसदी), व ग्लादेश (18.1 फीसदी) और चीन (13.3 फीसदी) में निर्यात बढ़ा। इससे इस माह में भारत के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि के दौरान हॉन्गकॉन्ग को निर्यात 27.9 फीसदी गिर गया।

फरवरी में इन 10 शीर्ष देशों को हुआ निर्यात

	(अरब डॉलर में)	सालाना आधार पर वृद्धि का %
अमेरिका	7.2	22
यूएई	3.5	23.1
नीदरलैंड	2.75	26.7
सिंगापुर	1.85	51.6
चीन	1.6	13.3
सऊदी अरब	1.3	50
ब्रिटेन	1.2	31.9
दक्षिण अमेरिका	1.16	100
बांग्लादेश	1.1	18.1
हॉन्गकॉन्ग	1.1	-27.9

स्रोत : वाणिज्य विभाग, बीएस की गणना

बढ़ता निर्यात

- वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद दिसंबर से लगातार तीन महीनों तक निर्यात में इजाफा
- जनवरी में अमेरिका को सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाला उत्पाद स्मार्टफोन हो गया
- अप्रैल-जनवरी के दौरान भारत से स्मार्टफोन के निर्यात का शीर्ष गंतव्य अमेरिका रहा
- फरवरी के दौरान भारत से हॉन्गकॉन्ग को निर्यात 27.9 प्रतिशत गिर गया

भारत के 2,000 डॉक्टरों को नौकरी देगा ब्रिटेन

अंजलि सिंह
मुंबई, 17 मार्च

ब्रिटेन की नैशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) बहुत जल्दी ही 2,000 भारतीय डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। इस उद्योग के सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन में डॉक्टरों की अत्यधिक कमी होने के कारण यह कदम उठाया गया है।

एनएचएस पहले बैच के डॉक्टरों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षण शुरू करेगी और प्रशिक्षण पूरा करने के 6 से 12 महीने के बाद इनकी नियुक्ति अस्पतालों में की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि यह प्रशिक्षण पूरा करने पर डॉक्टरों को प्रोफेशनल ऐंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट्स बोर्ड (पीएलएबी) परीक्षा से छूट मिलेगी। हालांकि इस पहल को एनएचएस में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के रूप में देखा जा रहा है जबकि कुछ अन्य इसे भारत के स्वास्थ्य सेवा में संभावित प्रतिभा पलायन के रूप में देखते हैं।

उजाला सिग्नस समूह अस्पताल के इंटरनल मेडिसन के डॉक्टर शुचिन बजाज ने कहा, 'इस कदम का भारत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह संख्या बेहद कम 2000 है। भारत में हर साल 1,10,000 डॉक्टर पढ़कर निकलते हैं। एनएचएस के इस कदम से वहां डॉक्टरों के स्थायी रूप से बसाए जाने की गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसे डॉक्टरों को बहुमूल्य अनुभव हासिल हो सकता है।' उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुभव के इस लेन-देन से भारत और ब्रिटेन दोनों देश लाभान्वित होंगे।

एनएचएस से बेहद करीबी रूप से जुड़े हुए डॉक्टर रवि बैज ने बताया कि एनएचएस का लंबे समय से विदेशी डॉक्टरों पर निर्भर रहने का इतिहास रहा है। एनएचएस में करीब 25 से 30 फीसदी डॉक्टर गैर यूके प्रशिक्षित डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा, 'एनएचएस दीर्घावधि में अपने डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए भी निवेश कर रही है। मेरे विचार से इस पहल से भारत से ज्यादा डॉक्टर ब्रिटेन आने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वित्तीय रूप से अब ब्रिटेन का ज्यादा आकर्षण नहीं रह गया है। एनएचएस की नजर भविष्य में विदेश के डॉक्टरों की संख्या कम करने पर है।'

एनएचएस ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भारत के प्रमुख शहरों के नामचीन अस्पतालों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। इस क्रम में दिल्ली, नागपुर, गुरुग्राम, कालीकट, बेंगलूरू, चेन्नई, इंदौर और मैसूर के प्रमुख अस्पतालों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

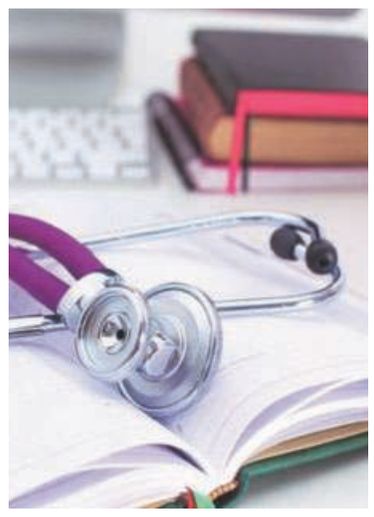

ब्रिटेन में डॉक्टरों की कमी

- एनएचएस ने भारत के प्रमुख शहरों के नामचीन अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षण शुरू किए
- यह प्रशिक्षण पूरा करने पर डॉक्टरों को प्रोफेशनल ऐंड लिंग्विस्टिक असेस्मेंट्स बोर्ड (पीएलएबी) परीक्षा से छूट मिलेगी
- पहल ब्रिटेन में डॉक्टरों की कमी को ही पूरा नहीं करेगा बल्कि भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के कौशल को भी बढ़ाएगा

डॉक्टर रवि ने कहा, 'भारत के डॉक्टरों के ब्रिटेन जाने से प्रतिभा पलायन हो सकता है। लिहाजा यह भारत सरकार के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है कि इस सिलसिले में कदम उठाए। भारत अपने यहां प्रशिक्षत डॉक्टरों को देश में पर्याप्त अवसर मुहैया करवाए। इस क्रम में डॉक्टरों को उनके कौशल के अनुसार पर्याप्त वेतन पैकेज मुहैया करवाया जाए ताकि वे प्रोफेशनल मानदंडों का पालन करते हुए अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें।'

इस पहल के बारे में जागरूकता कम है। हालांकि भारत के अस्पतालों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं लेकिन इस पहल का प्रचार सीमित हुआ है। लिहाजा डॉक्टर समुदाय के कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। बजाज के अनुसार इसका कारण ब्रिटिश संस्थानों का पारंपरिक नजरिया है।

हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में वरिष्ठ परामर्शदाता सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट अजेश राज सक्सेना ने कहा कि यह पहल ब्रिटेन में डॉक्टरों की कमी को ही पूरा नहीं करेगा बल्कि भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के कौशल को भी बढ़ाएगा।

भारत की मौजूदा आर्थिक तेजी का दौर 2003-07 जैसा

निवेश के दम पर आगे बढ़ रही भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार 2003-07 जैसी लग रही है। उस समय आर्थिक वृद्धि दर औसतन आठ प्रतिशत से अधिक थी। मॉर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही है।

मॉर्गन स्टेनली ने रिपोर्ट 'द व्यूपॉइंट: इंडिया - व्हाई दिस फील लाइक 2003-07' में कहा कि एक दशक तक जीडीपी के मुकाबले निवेश में लगातार गिरावट के बाद अब भारत में पूंजीगत व्यय वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'हमें लगता है कि पूंजीगत व्यय चक्र के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और इसलिए वर्तमान तेजी 2003-07 के समान है।' मॉर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वर्तमान तेजी खपत की तुलना में निवेश बढ़ने के चलते है। शुरुआत में इसे सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से समर्थन मिला, लेकिन निजी पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हो रही है। इसी तरह खपत को पहले शहरी उपभोक्ताओं ने सहारा दिया और बाद में ग्रामीण मांग भी बढ़ी। वैश्विक निर्यात में बाजार हिस्सेदारी बढ़ने और व्यापक आर्थिक स्थिरता से भी अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमारा मानना है कि मौजूदा तेजी जीडीपी के मुकाबले निवेश बढ़ने के चलते है। इसी तरह के वृद्धि चक्र में 2003-07 के दौरान जीडीपी के मुकाबले निवेश 27 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया था।' जीडीपी के मुकाबले निवेश 2011 तक अपने उच्चस्तर पर था, जिसके बाद इसमें गिरावट आई। *भाषा*

मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट

- एक दशक तक जीडीपी के मुकाबले निवेश में लगातार गिरावट के बाद अब भारत में पूंजीगत व्यय वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभरा है

एकाधिकार खत्म होने पर भी प्राकृतिक गैस क्षेत्र में बदलाव नहीं

अमृता पिल्लै और शुभायन चक्रवर्ती
मुंबई/नई दिल्ली, 17 मार्च

भारत में प्राकृतिक गैस के नियामक ने कुछ शहरों की गैस मार्केट के आधारभूत ढांचे की एक्सक्लूसिविटी (विशेष अधिकार) की अवधि खत्म होने का नोटिस इस महीने की शुरुआत में जारी करके इस उद्योग को आचंभित कर दिया था। लेकिन उद्योग के जानकारों के अनुसार यह अप्रत्याशित कदम उठाए जाने के बाद भी प्रतिस्पर्धा की यथास्थिति में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 4 मार्च को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा कि मुंबई और ग्रेटर मुंबई के भौगोलिक क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचा एक्सक्लूसिविटी की मियाद खत्म हो चुकी है। इस समय अवधि को अप्रैल 2021 में ही खत्म होने की बात कही गई थी।

पीएनजीआरबी के खिलाफ दायर मामले में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे क्लारस लॉ एसोसिएट्स के वकील पीयूष जोशी ने कहा, 'शहरी गैस वितरण कंपनियों के मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी पर पहले से ही मामला दर्ज है। हालांकि मार्च के नोटिस में पहली बार बुनियादी ढांचे की एक्सक्लूसिविटी का मुद्दा उठाया गया है।' उन्होंने कहा, 'पीएनजीआरबी के बोर्ड में कानूनी क्षेत्र का कोई सदस्य नहीं है और इसके द्वारा पहले अधिसूचित साझे कैरियर के बारे में विनियमन पर भी मामला दर्ज है। ऐसे में यह नोटिस आश्चर्यचकित करने वाला है।'

पीएनजीआरबी ने ईमेल से भेजे जवाब में कानूनी क्षेत्र के सदस्य पर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन उसने कहा, 'कुछ भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) के लिए आधारभूत ढांचे की एक्सक्लूसिविटी की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन इकाइयों ने अवधि के विस्तार के लिए पीएनजीआरबी के समक्ष आवेदन नहीं किया है। इसलिए 4 मार्च 2024 की नोटिस के अनुसार ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों के लिए इन्फ्रा एक्सक्लूसिविटी की अवधि समाप्त हो चुकी है। लेकिन यदि किसी कंपनी ने विस्तार के लिए आवेदन किया है तो पीएनजीआरबी अधिनियम और विनियमन के तहत उस पर विचार किया जा सकता है।'

महाराष्ट्र गैस को गुरुवार हमने ईमेल भेजा था, लेकिन उसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। इन नोटिस के कारण महानगर गैस के शेयर के मूल्य पर भी असर पड़ा और वह गुरुवार को 1279 तथा शुक्रवार को 1270 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

नुवामा के विश्लेषकों के अनुसार शेयर को संभलने का समय तक नहीं मिला। विश्लेषकों के अनुसार, 'पीएनजीआरबी के अनुसार एमजीएल का मुंबई में एकाधिकार अप्रैल, 2021 में ही खत्म हो गया था। हमारा तर्क है कि पूर्ववर्तियों की तरह इसका 10 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है।

बाजार में नए प्रवेश करने वाले उन स्थानों पर मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, जहां महानगर पहले से ही वितरण कर रहा है। इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा कम से कम है। अदालत में लंबित मामलों का जब तक निपटारा नहीं हो जाता, तब तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ा जा सकता।'

उद्योग के वरिष्ठ अधिकारीगण और विश्लेषक न्यूनतम प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से सहमत हैं।

आईसीआरए के कॉरपोरेट रेटिंग्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सह-समूह प्रमुख ग्रुप प्रशांत वशिष्ठ ने बताया, 'तकनीकी रूप से पिछले कई वर्षों से ज्यादातर सीजीडी मार्केट के लिए तीसरे पक्ष की मार्केटिंग खुली हुई है लेकिन इन सर्कलों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

बाजार में नए प्रवेश करने वालों के समक्ष दो बाधाएं हैं। पहला, मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी का मामला अदालत में विचाराधीन है और दूसरा, गैर व्यापारिक बाधाओं की आशंका को लेकर असहजता है।' भारत में इंदौर, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद उन शहरों में हैं मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी कई साल पहले खत्म होने की बात की जा रही है, वहां कई गैस कंपनियां हैं।

विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में मुकदमेबाजी बढ़ेगी जबकि अभी कुछ मुकदमें लंबित हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नोटिस

- एक्सक्लूसिविटी का मतलब है किसी एक भौगोलिक इलाके में सिर्फ एक कंपनी को कारोबार का अधिकार, इसके लिए उसे विशेष सहूलियत या एकाधिकार
- मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी : कॉमन कैरियर या कॉन्ट्रैक्टकैरियर के दायरे में विशेष अधिकार
- कॉमन कैरियर क्षमता : सीजीडी नेटवर्क में अधिकृत इकाई की अपनी आवश्यकताओं और फर्म के अनुबंध के आधार पर आवंटित क्षमता के अतिरिक्त क्षमता मिलना
- आधारभूत ढांचा एक्सक्लूसिविटी : बुनियादी ढांचे का एकाधिकार, कोई भी तीसरा पक्ष उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए किसी तरह के बुनियादी ढांचा के तहत बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार का कार्य नहीं कर सकता

स्रोत – पीएनजीआरबी

बीएस सूडोकू 4924

परिणाम संख्या 4923

1	9		4		6			
			3			9	4	1
	4		1		7		5	
		1			8	5	7	3
				2	3			6
			5	6		4	9	
		3				7		
7		4				2	6	9
	8	5	6		9		3	

2	8	5	9	7	1	6	3	4
3	4	9	2	6	8	1	7	5
1	7	6	4	3	5	9	8	2
4	6	2	1	9	7	3	5	8
8	9	3	6	5	4	7	2	1
7	5	1	3	8	2	4	9	6
5	1	8	7	4	9	2	6	3
6	2	7	5	1	3	8	4	9
9	3	4	8	2	6	5	1	7

कैसे खेलें ? **मध्यम**

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

अप्रैल – मई में क्रेडिट कॉर्ड पेश करेगा बंधन बैंक

मनोजित साहा
मुंबई, 17 मार्च

प्राइवेट क्षेत्र का ऋणदाता बंधन बैंक जल्द ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा और अप्रैल या मई में वह इसका ऐलान करेगा। बंधन बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के पूर्व एक्जीक्यूटिव पीयूष झा को क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का प्रमुख बनाया है। पीयूष झा बीओबी फाइनैंशियल सोल्यूशंस लिमिटेड से जुड़े थे। कोलकाता स्थित ऋणदाता में कई बैंकर शामिल हुए हैं।

बंधन बैंक बीते 10 वर्षों से कारोबार कर रहा है लेकिन वह यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले नवीनतम ऋणदाताओं में से एक है। बंधन बैंक ने अगस्त 2015 में कारोबार शुरू किया था।

बंधन में हुई प्रमुख नियुक्तियों में से एक राजिंदर कुमार बब्बर की नियुक्ति एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐंड चीफ बिजनेस ऑफिसर के पद पर हुई है। भारत के क्रेडिट कार्ड बाजार में 70 फीसदी हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की है। जनवरी, 2024 तक देश में कुल 9.95 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे।

बंधन बैंक में शीर्ष पदों पर हाल में हुई नियुक्तियां

नाम	पद	यहां दी हैं सेवाएं
राजिंदर कुमार बब्बर	एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर ऐंड चीफ बिज़नेस ऑफिसर	एचडीएफसी बैंक
राजीव मंत्री	चीफ फाइनैंशियल ऑफिसर	सिटी
पीयूष झा	हेड, क्रेडिट कार्ड	बीओबी फाइनैंशियल सोल्यूशंस
पिनाकी हलधर	चीफ इन्फार्मेशन ऑफिसर	एक्सिस बैंक
संतोष नायर	हेड ऑफ कंज्यूमर लैंडिंग ऐंड मोटरगेज	एचडीएफसी सेल्स
राजेश कुमार श्रीवास्तव	हेड, बैंक कंट्रोल यूनिट	सूर्योदय एसएफबी
राधिका राघवन	हेड, कस्टमर एक्सपीरियंस	बार्कले शेयरड सर्विसिज

डिस्क्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 27

आचार संहिता की चुनौती

एक महीने से कुछ अधिक समय के भीतर देश में दूसरे सबसे लंबे आम चुनावों का सिलसिला आरंभ हो जाएगा। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का बड़ा उत्सव होगा। भारत जैसे विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश के लिए इस पंचवर्षीय आयोजन का पैमाना कभी कम नहीं था। 2024 के चुनाव का आकार अपने पूर्ववर्तियों को छोटा साबित कर देगा। सात चरणों में होने जा रहे आम चुनावों के लिए करीब 96.9 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इसके साथ ही चार राज्यों के विधान सभा चुनाव भी होंगे। यह आंकड़ा देश की चुनावी कवायद को इस वर्ष अन्य बड़े लोकतांत्रिक देशों में होने जा रहे चुनावों की तुलना में बड़ा बनाने वाला है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। वहां करीब 20.4 करोड़ मतदाता हैं। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश है वहां करीब 16.8 करोड़ मतदाता हैं। भारत में कुल मतदाताओं में आधी संख्या महिलाओं की है। अनुमान के मुताबिक ही इन मतदाताओं में जो गरीब हैं वे प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के निशाने पर हैं। इन चुनावों में युवाओं की अहम भूमिका होगी क्योंकि करीब 29 फीसदी मतदाता 18 से 29 वर्ष की आयु के हैं। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि भारत में करीब दो लाख मतदाताओं की आयु 100 वर्ष से अधिक है। यह एक तथ्य है कि भारत इतने बड़े चुनावों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिये अंजाम देने में कामयाब रहता आया है और हमारे ऊपर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की तरह मत पत्रों की हेराफेरी या चोरी जैसे कोई इल्जाम नहीं लगे। इस लिहाज से भारत का प्रदर्शन सराहनीय है।

कुछ चिंता की बातें भी हैं और उनमें से प्रमुख है भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता की निगरानी और उसे प्रभावी ढंग से लागू कराने की क्षमता। इस लिहाज से देखा जाए तो चुनाव प्रक्रिया को लंबा बनाना मसलन 1999 के 29 दिन से 2019 में 39 दिन और 2024 में उसे 44 दिन करना प्रमुख विपक्षी दलों के बीच विवाद का विषय है। चुनाव आयोग ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि कई चरणों में चुनाव कराना इसलिए आवश्यक है ताकि बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर तैनात किया जा सके।

चुनावों को अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग 1.5 करोड़ मतदानकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की सेवाएं लेता है। चुनाव प्रचार अभियान की आवृत्ति और गहनता को देखते हुए यह यह उम्मीद करना कठिन है कि वह इस बात की प्रभावी निगरानी करे कि सभी दल आचार संहिता का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। चरणबद्ध मतदान भी सवाल पैदा करते हैं। प्रमुख आशंका यह है कि लंबी अवधि तक विस्तारित चुनाव सत्ताधारी दल को असंगत रूप से फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि उसके पास सरकारी अधोसंरचना होती है जिसका वह चुनाव प्रचार में फायदा उठा सकता है।

एक और विषय जिस पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है वह है टेलीविजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया और फोन का प्रचार उपकरणों के रूप में इस्तेमाल। लंबे समय तक चलने वाले चुनावों में ऐसे आभासी प्रचार प्रतिस्पर्धी दलों को यह अवसर देते हैं कि वे उन इलाकों में भी अपने प्रचार को बढ़ा सके जहां चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार रोक दिया जाना चाहिए। अधिकांश दल चतुराईपूर्ण तरीके से इन प्रचार तकनीकों का इस्तेमाल करके प्रचार पर रोक को धता बताने की कोशिश करते हैं। ये वे चुनौतियां हैं जिनसे निर्वाचन आयोग को शीघ्र निपटने की आवश्यकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए भी मशविरा जारी किया है। उदाहरण के लिए उसने सलाह दी है कि प्रचार अभियान मुद्दों पर आधारित होना चाहिए और राजनीतिक दलों को नफरत फैलाने वाले भाषण देने से बचना चाहिए। मतदान की अपीलें जाति और धर्म के आधार पर नहीं की जानी चाहिए और यह प्रमुख चुनाव प्रचारकों की जिम्मेदारी है कि वे शुचिता बनाए रखें। चूंकि चुनाव प्रतिस्पर्धी होते हैं, ऐसे में यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि हर कोई नियम कायदों का पालन करे।

अजय मोहंती

सीएए मामला: बासी कढ़ी में संभव है उबाल?

भारतीय जनता पार्टी के लिए सीएए एक रणनीतिक कदम था जो कारगर नहीं साबित हुआ क्योंकि जिन्हें इस कानून से लाभ होता उन्हें दूसरे मौजूदा कानूनों की मदद से भी समायोजित किया जा सकता है

मोदी सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के नियमों को लागू करने की जो अधिसूचना जारी की वह अपना तात्कालिक उद्देश्य पूरा नहीं कर सकी। यानी वह बेनामी चुनावी बॉन्ड से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दबा नहीं पाई। बॉन्ड के मामले में उभरने की पूरी क्षमता थी।

सीएए तब तक मृत प्राय था जब तक दो घटनाएं नहीं घट गईं। पहला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून पर हमला करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लाखों गरीब अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों के लिए निमंत्रण की तरह है। इस बयान के बाद उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया। ये वे हिंदू हैं जो दिल्ली की अवैध बस्तियों में अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं। इससे भी अहम भूमिका अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे दोबारा सुर्खियों में लाकर की। उसके प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपनी सामान्य ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका इस कानून से चिंतित है। वह सभी आस्थाओं को मानने वालों की समता के पक्ष में खड़ा है और वह इसका नजदीकी से अध्ययन कर रहा है। ऐसे में मैं उनसे और विदेश मंत्रालय में बैठे उनके वरिष्ठों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि इसके गहरे अध्ययन के बाद अगर वे कुछ गलत पाएं तो हमें भी समझाएं। या फिर जैसा कि किशोर कुमार ने सन 1965 में आई देव आनंद की फिल्म तीन देवियां में मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों में गाया था, '...अगर इसे समझ सको, मुझे भी समझाना।'

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

तथ्य यह है कि बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद भी मुझे यह निर्णय करने में मुश्किल हुई कि सीएए अच्छा है, बुरा है, थोड़ा-थोड़ा दोनों है या फिर यह बेमानी है। कोशिश करते हैं कि इसे इसके संभावित लाभार्थियों, पीड़ितों या सैद्धांतिक दलीलें पेश करने वालों के नजरिये से परखा जाए।

■ इसके संभावित लाभार्थियों में से अधिकांश हिंदू और कुछ सिख, ईसाई और शायद थोड़े बहुत बौद्ध हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। इसके तय आंकड़े पता लगा पाना मुश्किल है। हालांकि भारत के उलट पाकिस्तान ने 2023 में जनगणना कराई थी। समझ को आसान बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि यह आंकड़ा करीब दो करोड़ का है जिसमें 95 फीसदी से अधिक हिंदू हैं। मान लेते हैं कि उनमें से अधिकांश या कोई भी बुरी तरह प्रताड़ित महसूस कर रहा हो और भारत आना चाहता हो तो क्या वह सीएए से खुश नहीं होगा? दुर्भाग्यवश इसका उत्तर न है। उन्हें 10 वर्ष से अधिक की देरी हो चुकी है। यह कानून उन्हें तभी फायदा पहुंचाता जब वे 2014 के अंत के पहले भारत आ चुके होते क्योंकि इसके आवेदन के लिए 31 दिसंबर, 2014 को आखिरी तारीख घोषित किया गया है।

■ क्या 2014 की उपरोक्त तारीख से पहले भारत आने वालों को फायदा मिलेगा ही मिलेगा? उन्हें यकीनन लाभ मिल सकता है लेकिन वे एक सवाल पूछ सकते हैं: अगर भारत, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार को वास्तव में उनकी इतनी अधिक चिंता थी तो उसने बीते 10 वर्षों में उन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी? भारत सरकार के पास किसी को भी नागरिकता प्रदान करने के संप्रभु अधिकार हैं। किसी खास समुदाय के लिए विशेष कानून की आवश्यकता नहीं। गायक अदनान सामी को भारत की नागरिकता देने के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं थी। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत धूमधाम से उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की थी। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के गरीब और बदहाल हिंदुओं को इतने सालों तक अमानवीय परिस्थितियों में क्यों जीवन जीने दिया गया? उसके बाद भाजपा की राजनीति में उन्हें 10 वर्ष तक और इंतजार कराया गया ताकि एक अनुकूल अवसर पर इस कानून को लाया जा सके?

■ संभावित लाभार्थियों की बात करने के बाद हम बात करते हैं उनकी जिन्हें इससे डर है। अब शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए कि 2019 के प्रावधान अब मौजूद नहीं हैं। उस वक्त सीएए देशव्यापी स्तर पर एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। एनआरसी का डर अब समाप्त हो चुका है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 22 दिसंबर, 2019 को रामलीला मैदान में अपने भाषण में इसका मखौल उड़ा दिया था। अहसास हो गया था कि पार्टी ने इसे लंबा खींच दिया है। इसे लेकर नकार तब स्पष्ट हो गया जब प्रधानमंत्री प्रमुख इस्लामिक देशों से सर्वोच्च सम्मान ले रहे थे और पाकिस्तान से इतर अरब देशों से अपने नए रिश्तों का महत्त्व समझा रहे थे। तब से भाजपा के किसी नेता ने इसे नहीं उठाया है। अगर एनआरसी नहीं है तो भारत के किसी मुस्लिम को डरने की जरूरत नहीं।

■ यह कानून केवल असम में असर डाल सकता है। भारतीय नागरिकता कानून में एक के बाद एक संशोधनों से असम को अलग रखा गया। ऐसा राज्य में अवैध प्रवासियों (जिसे बाद में विदेशी विरोधी कहा गया) के खिलाफ व्यापक आंदोलन के कारण किया गया जो 1979 से आरंभ हुआ था। ब्रह्मपुत्र घाटी के मूल असमी भाषियों द्वारा और जनजातीय इलाकों में माना जाता है कि लाखों बांग्लादेशी उनके राज्य में बस गए हैं और जनांकीय संतुलन को खराब कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राज्य में चार दशक से अधिक समय तक काम किया और असमी हिंदुओं को यह यकीन दिलाने का प्रयास किया कि उन्हें बंगाली मुस्लिमों और हिंदुओं में भेद करना चाहिए। इसमें कामयाबी मिली लेकिन पूरी नहीं। असम में अंतर यह है कि एनआरसी की प्रक्रिया को वहां पहले ही अंजाम दिया जा चुका है। असम दोहरे जाल में फंस गया। पहले तो एनआरसी में बड़ी तादाद में हिंदू भी मुश्किल में आ गए। भाजपा और आरएसएस के उभार के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में असम के लोगों खासकर छात्रों के लिए अभी भी बंगाली हिंदू एक मसला हैं। वे उन्हें स्वीकारना नहीं चाहते। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा नए असंतोष को समाप्त करने के लिए कह रहे हैं कि लाखों बंगाली हिंदुओं को शामिल करने की बात मूर्खतापूर्ण है। वह कहते हैं कि केवल बराक घाटी के 50 से 80 हजार हिंदुओं को ही शामिल किया जा सकता है। ऐसे में लग सकता है कि अगर इस राजनीतिक रूप से विभाजनकारी कानून से केवल इतने लोगों को लाभ होना था तो भला इसकी क्या जरूरत थी?

यह नतीजा निकालना सही होगा कि भाजपा के लिए यह एक रणनीतिक कदम था जो कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि जिन्हें इससे लाभ मिलना था उन्हें मौजूदा कानूनों के तहत ही आसानी से शामिल किया जा सकता था और नए आने वालों को बाहर रखा जा सकता था। देशव्यापी ध्रुवीकरण और सड़कों पर असंतोष की उम्मीद तब समाप्त हो गई जब प्रधानमंत्री ने खुद एनआरसी को इससे बाहर कर दिया। मुस्लिम समुदाय ने भी परिपक्वता दिखाई और ताजा घटनाक्रम को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह संवैधानिक तर्क बाकी है कि क्या धर्म के आधार पर नागरिकता तय हो सकती है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई जारी रहेगी। फैसला चाहे जो भी हो यह अकादमिक होगा और इससे कोई खास अंतर नहीं होगा।

नागरिकता प्रमाणपत्र देते समय समारोह आदि होंगे। उसके अलावा सीएए की कहानी में अब दम नहीं बचा है। यह दो स्थितियों में नए सिरे से उभर सकती है: देशव्यापी एनआरसी की नए सिरे से चर्चा और अथवा इसकी तय तारीख को 31 दिसंबर, 2014 से बदलना। क्या ऐसा हो सकता है? मेरा मानना है कि 2029 के चुनाव के पहले इस पर नजर रखी जाए।

चुनावों से निकले जनादेश और उनमें बदलाव

दुनिया के पांच बड़े देशों में से चार- भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान-में 2024 में या तो चुनाव होंगे या हो चुके हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव यानी यूरोपीय संसद के चुनाव भी होने हैं। मैक्सिको, रूस और यूनाइटेड किंगडम सहित दुनिया के कई अन्य बड़े तथा प्रभावशाली देशों में ऐसे चुनाव होने हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी। 'लोकतंत्र' शब्द जितना बताता है उससे कहीं अधिक छिपाता है। ये सभी चुनाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। रूस जैसे कुछ देशों में होने वाले चुनाव दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले चुनावों की तरह ही संस्थागत प्रक्रिया नजर आते हैं लेकिन वास्तव में वे एक निरंतर अधिनायकवादी होती व्यवस्था के अधीन होने वाले चुनाव हैं। अन्य चुनाव मसलन पाकिस्तान में होने वाले चुनावों में शक्तिशाली संविधान से इतर ताकतों का हस्तक्षेप है। भारत में फंड जुटाने से लेकर मीडिया तक एक पक्ष का दबदबा होने के कारण यह कहना मुश्किल है कि हमारे यहां होने वाले स्वतंत्र चुनाव वास्तव में पूरी तरह निष्पक्ष भी हैं।

परंतु एक अन्य अंतर है जिस पर विचार करना आवश्यक है: विभिन्न देशों और ब्लॉक का अंतर यानी जहां चुनाव नतीजों का अनुमान लगाया जा सकता है तथा जहां अनुमान नहीं लगाया जा सकता है या दूसरे शब्दों में कहें ऐसे देश और ब्लॉक जो स्पष्ट जनादेश देते हैं तथा दूसरे वे जो ऐसा नहीं करते हैं, उनके बीच का अंतर। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में इस वर्ष के आरंभ में हुए राष्ट्रपति चुनाव में प्रबोवो सुबिआंतो को 58 फीसदी मत मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 25 फीसदी मत भी नहीं मिले। यानी यह बात उन्हें शासन करने का स्पष्ट जनादेश देती है। सबसे आशावादी समर्थक भी यह दावा नहीं कर सकते कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन या डॉनल्ड ट्रंप को ऐसा ही जनादेश मिल सकेगा। सबसे अधिक संभव परिदृश्य यही है कि ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बन जाएं लेकिन शायद उन्हें बहुत अधिक मत न मिलें। संघीय स्तर पर अमेरिका तेजी से निष्क्रिय हो गया है क्योंकि वह अब लगातार अपने विजेताओं को सशक्त जनादेश देने में विफल रहता है।

नीति नियम
मिहिर शर्मा

इस बीच यूनाइटेड किंगडम में हुए हालिया चुनाव इसके विपरीत चीजें दर्शाते हैं। लेबर पार्टी को इस समय 28 अंकों की अविश्वसनीय बढ़त हासिल है। अगर इसे सीटों में बदलने में कामयाबी मिली तो सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी आगामी संसदीय चुनावों में तीसरे या चौथे स्थान पर सिमट सकती है। ऐसे ही घटनाक्रम में कुछ राजनीतिक दल इतिहास के पन्नों से गायब ही हो गए। कनाडा की कंजरवेटिव पार्टी के सदस्य यानी टोरीज 1993 के घटनाक्रम से भयभीत हैं जब 1980 के दशक से अधिकांश समय देश पर शासन करने वाले प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव के खिलाफ 27 फीसदी मत परिवर्तन हुआ था और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनका पतन ही हो गया था। लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टार्मर के इस बात की चिंता करने की संभावना नहीं है कि उन्हें मिलने वाला जनादेश बड़े सुधारों की शक्ति प्रदान करेगा या नहीं।

यूरोपीय संसद का मामला अलग है। यूरोपीय संघ की विधायी संस्था दरअसल यूरोप के प्रति आशंका रखने वालों का एक प्रतिवाद है। जैसा कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते के वार्ताकार जानते हैं कि यूरोपीय संसद इस बात के लिहाज से काफी महत्त्वपूर्ण है कि आखिर यूरोपीय किस तरह की रियायतों पर सहमत हो सकते हैं। परंतु कुछ सदस्य देशों की राजनीति में अहम बदलाव के बावजूद यानी फ्रांस, इटली और जर्मनी में धुर दक्षिणपंथ के उभार के बावजूद ताजा चुनाव यही सुझाते हैं कि राजनीतिक चुनाव खुद को खारिज कर सकते हैं और मध्य दक्षिण और मध्य वाम ब्लॉक संसद में पिछले साल की तरह ही सीटें हासिल कर सकते हैं। यूरोपीय चुनाव जहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिनिधित्व वाले हैं, वहीं यह प्रभाव भी एक वजह है जिसके चलते कुछ लोगों का मत अलग है यानी उन्हें नहीं लगता कि उनके चुनावों में बड़ा या स्पष्ट जनादेश मिलेगा।

यह बात हमें एक बुनियादी नतीजे की ओर ले जाती है: लोकतंत्र में विश्वास को बहाल रखने के लिए चुनावों का केवल हस्तक्षेप से स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें यह क्षमता भी दर्शानी चाहिए कि वे निर्णायक जनादेश दे सकते हैं और उनमें विपक्ष के पक्ष में बड़ा मत प्रतिशत स्थानांतरित करने की भी क्षमता है। भारत में बीते एक दशक में हमें निर्णायक जनादेश मिले हैं लेकिन इस बात को लेकर हमारा संदेह बढ़ता जा रहा है कि सत्ताधारी दल के विरुद्ध मत परिवर्तन संभव भी है या नहीं। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि यह चुनावी मौसम खासतौर पर दिलचस्पी से रहित और नीरस है क्योंकि इसमें पिछले चुनावों की तरह उत्साह और अनिश्चितता का माहौल नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो यह शिकायत अस्पष्ट नजर आती है। परंतु इसमें कहीं अधिक गहरी सच्चाई छिपी हुई है: लोकतांत्रिक देशों में लोगों को अनिश्चितता की भावना की आवश्यकता है ताकि उन्हें यह विश्वास हो कि उनकी आवाज और उनके वोट मायने रखते हैं। एक बार चुनाव हो जाने के बाद उन्हें अपने जीवन में वापस लौटने और अपने प्रतिनिधियों को सरकार के कामकाज में भाग लेने देने के लिए जनादेश को देखने की आवश्यकता होती है।

आपका पक्ष

बेंगलूरु जल संकट को समझना जरूरी

कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु आजकल जल संकट से जूझ रही है। वहां के मुख्य व्हाइटफील्ड, येलहंका और कनकपुरा में स्थिति बहुत ही खराब है। खबर यह भी है कि उन क्षेत्रों में टैंकरों से जल की सप्लाई की जा रही है। संकट को देखते हुए वहां कुछ संस्थाओं ने जल की बरबादी करने वाले लोगों पर हजारों रुपये का जुर्माना भी घोषित कर दिया है। कुछ समय पहले नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी कि हमारे देश में 2030 तक 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने का साफ जल नहीं मिलेगा। यह काफी चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट ऐंड ह्यूमन सिक्योरिटी की इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में बताया गया है कि वर्ष 2025 तक हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में जल संकट गहरा सकता है और भूजल संकट पैदा हो सकता है। जल संकट का मुख्य कारण इसका बेहिसाब दोहन है। संकट से निपटने

बेंगलूरु में इन दिनों जारी जल संकट के बीच स्थानीय लोग पानी के टैंकर से पानी भरते हुए

के लिए जल बचाने और बारिश के जल को संभालने के लिए भी उपाय बताए और किए जाते हैं, जो कि अच्छा प्रयास भी है। कम बारिश कृषि के लिए भी और जल संकट पैदा करने वाली होती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई कहीं जल संरक्षण की बात करे तो उसे साथ में प्रकृति बचाने की भी बात जरूर करनी चाहिए। प्रकृति का दोहन बंद होगा तो समय पर बारिश होगी। अगर समय पर और उचित मात्रा में बारिश होगी तो यह देश को जलसंकट से बचाने में मददगार साबित होगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेहनती अभ्यर्थियों के साथ न्याय की दरकार

देश के ज्यादातर युवा सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। बीते कुछ वक्त से सरकारी नौकरियों के लिए अमल में लाई जा रही भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही है। कभी पेपर लीक तो कभी प्रश्न पत्र की खरीद-फरोख्त। यह अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय होती है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कम से कम मानवीय हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर के माध्यम से ही ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत प्रश्न पत्र सेट किए जाएं। इसके अलावा, विभिन्न पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एस-एससी) परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को सरकारी पदों के लिए आवेदन करने में सुविधा हो। इससे न सिर्फ पारदर्शिता के नए मापदंड स्थापित होंगे बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का अधिकार भी प्राप्त होगा। विभिन्न राज्यों के राज्य चयन आयोग ऑनलाइन कंप्यूटर प्रक्रिया के तहत सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा करवाएं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित हों। उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी देने के लिए प्रैक्टिस लिंक भी उपलब्ध करवाए जाएं। पारंपरिक परीक्षाओं के स्थान पर कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं प्रारंभ होने से न केवल दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि सभी उम्मीदवारों के लिए एक निष्पक्ष और मानकीकृत मूल्यांकन मंच भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय नौसेना ने एक अभियान में सोमालिया के 35 समुद्री डाकुओं को पकड़ने और उनके द्वारा बंधक बनाए गए 17 लोगों को मुक्त कराने के एक दिन बाद रविवार को कहा कि यह कार्रवाई हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को मजबूत करने और क्षेत्र में समुद्री डकैती के फिर से सिर उठाने को विफल करने के उसके संकल्प को दर्शाती है। नौसेना ने शनिवार को एक सुव्यवस्थित अभियान में भारतीय तट से लगभग 2,600 किलोमीटर दूर पूर्व में माल्टा के ध्वजांकित व्यापारिक जहाज (एमवी) रुएन को मुक्त कराया।

एनएसई डेरिवेटिव में एफआईआई निवेश

	Week ended Mar 08		Week ended Mar 15	
	Contract (Nos)	Tovr (` bn)	Contract (Nos)	Tovr (` bn)
Index Future	391281	340.0	482872	419.0
Stock Future	2236182	1936.8	2675052	2259.4
Index Option	251782299	215876.2	291881354	254046.1
Stock Option	3312559	3091.8	4538709	4091.5
Total	257722321	221244.7	299577987	260379.6

बीएसई 500 कंपनियों में एफआईआई शेयरधारिता

IN %	Dec -22	Mar -22	Jun -22	Sep -23	Dec -23
Elgi Equipments	30.1	30.0	30.2	29.7	29.9
Emami	11.5	11.3	11.7	12.3	13.2
Endurance Technologies	7.7	7.7	7.4	8.4	7.9
Engineers India	8.8	8.9	8.5	8.7	8.5
Epigral	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6
EPL	12.8	12.6	12.8	11.0	10.5
Equitas Small Finance Bank	4.3	26.7	25.6	22.4	23.7
ERIS Lifesciences	15.7	15.1	14.0	13.5	13.4
Escorts Kubota	4.4	5.2	6.2	7.3	5.6
Exide Industries	11.9	13.2	13.7	13.6	13.7
FDC	4.8	4.9	3.2	3.6	3.8
Federal Bank	33.2	32.5	31.9	32.0	34.2
Fertilizers & Chemicals	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
Fine Organic Industries	6.3	5.2	4.2	4.2	4.0
Finolex Cables	12.7	11.4	13.9	14.3	13.7
Finolex Industries	5.9	6.0	6.3	7.2	6.9
Firstsource Solutions	9.5	10.1	11.0	11.3	11.2
Five-Star Business Finance	50.6	51.0	51.6	50.7	54.8
Fortis Healthcare	31.3	31.5	30.4	26.7	24.1
FSN E-Commerce Ventures	26.5	26.4	22.9	20.8	21.1
G R Infraprojects	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6
GAIL (India)	18.1	16.5	16.2	14.9	14.4
Galaxy Surfactants	5.2	5.4	5.5	5.6	6.1

एफआईआई / डीआईआई निवेश

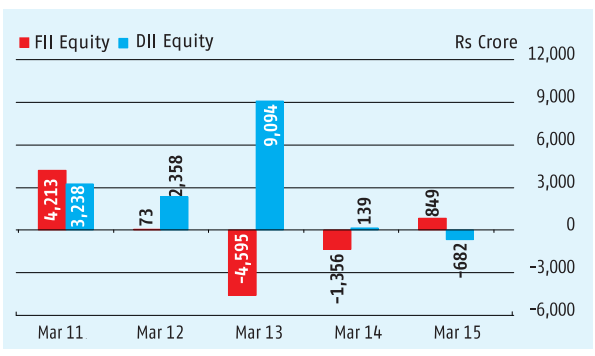

सप्ताह का शेयर (कोलगेट पामोलिव)

Hits new all-time high at Rs 2,748, Up 81 percent FYTD

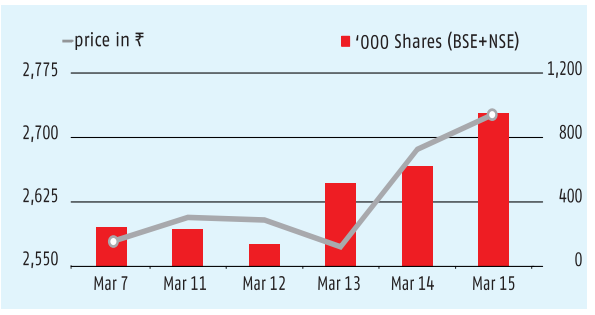

निफ्टी स्नैपशॉट

	Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 14	Mar 15
Nifty 50 Spot	22332.7	22335.7	21997.7	22146.7	22023.3
Nifty 50 Future	22421.4	22447.1	22103.3	22264.6	22133.2
Prem/Discount	88.7	111.4	105.6	117.9	109.8
Fut(Open Int)	15572	15645	16047	16211	16143
Fut(Contract)	140183	134590	265832	199017	228508
Fut(Value Rs Cr)	15777.3	15127.4	29573.3	22124.3	25292.1
PCR(Open Int)	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0
PCR(Contract)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Major Call(Strike Price)	23000.0	22500.0	22500.0	22150.0	23000.0
Major Call(LTP)	2.6	48.6	4.0	2.7	1.9
Major Put(Strike Price)	21000.0	22000.0	21700.0	22100.0	21000.0
Major Put(LTP)	12.5	11.5	7.9	1.0	2.4

पुट/कॉल रेशियो

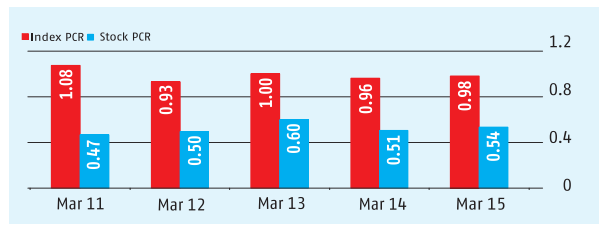

सेक्टर पर नजर

TOP GAINERS	OI '000	% chg	TOP LOSERS	OI '000	% chg
Air Transport Service	10764	59.6	Logistics	27424	18.1
Tyres	36046	47.8	Trading	41346	17.9
Consumer Durables	341284	41.4	Hotels & Restaurants	35574	17.6
Retail	5923	33.1	Refineries	597179	16.2
Power Generation &	620689	31.3	**Top Losers**		
Oil & gas	148686	28.5	Fertilizers	54005	-27.4
Engineering/CG	19365	28.3	Non Ferrous Metals	204663	-5.3
Tobacco Products	295187	27.7	Textiles	5655	-5.2
Mining & Mineral	394373	19.8	Entertainment	172606	-4.9
Castings, Forgings &	11857	18.6	Paints/Varnish	37433	-2.5
Leather	5860	18.2	Packaging	11621	-2.3

कीमत में बढ़ोतरी के साथ ओपन इंटरेस्ट

	Open Int as on			Price as on		
	Mar 08	Mar 15	% Chg	Mar 08	Mar 15	% Chg
InterGlobe Avia	5142300	7180200	39.6	3105.7	3203.1	3.1
Pidilite Ind	2693750	2132250	-20.8	2865.9	2868.0	0.1
Oracle Fin	977000	1179400	20.7	8301.8	8453.3	1.8
ITC	111552000	126968000	13.8	413.6	419.1	1.3
HDFC Std Life	29363400	26127200	-11.0	622.0	632.4	1.7
Persistent S	1466500	1613900	10.1	8372.1	8432.5	0.7
Colgate	3262000	3584700	9.9	2578.7	2728.6	5.8
Bajaj Fin	10216375	9223375	-9.7	6421.1	6514.4	1.5
HDFC Bank	223949000	203021500	-9.3	1446.1	1452.7	0.5
HDFC AMC	3002100	3266700	8.8	3745.8	3818.7	1.9
PI Inds	2030500	1853000	-8.7	3626.0	3649.2	0.6
Britannia	2531000	2310600	-8.7	4889.2	4974.2	1.7
TCS	12844125	13816250	7.6	4108.6	4219.3	2.7
Wipro	54537000	50752500	-6.9	515.5	517.0	0.3
Bosch	273500	254650	-6.9	29501.0	29571.6	0.2
LTIMindtree	2981250	2782800	-6.7	5122.7	5194.4	1.4
Siemens	991950	1057500	6.6	4668.7	4771.3	2.2
Polycab India	2062600	1943100	-5.8	4891.0	4894.5	0.1

एनएसई सूचकांक

	Mar 08	Mar 15	% Chg
SPOTNifty 50	22493.6	22023.3	-2.1
Bank Nifty	47835.8	46594.1	-2.6
Nifty IT	37099.9	37500.7	1.1
Futures (LTP)			
Nifty 50	22552.3	22133.2	-1.9
Bank Nifty	47958.3	46694.7	-2.6
Nifty IT	47958.3	46694.7	-2.6
Open Interest			
Nifty 50	15477900.0	16142950.0	4.3
Bank Nifty	4719405.0	5461305.0	15.7
Nifty IT	4719405.0	5461305.0	15.7

तेजी / गिरावट बीएसई

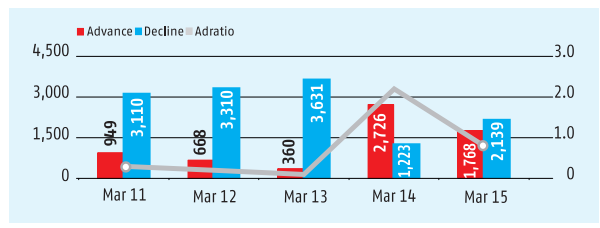

मार्केट पोजीशन

HIGHEST	OI	% of MWL	LOWEST	OI	% of MWL
Biocon	97482500	104.45	ICICI Lombard	3448500	6.75
HAL	19364700	102.10	Infosys	49941600	7.98
Hind Copper	65767700	100.44	L & T	25229100	9.09
Nestle India	6980800	97.22	Coromndl Int	2283400	9.11
NMDC	203953500	88.75	Godrej Cons	7105000	9.44
PVR	12560834	88.56	Sun Pharma	22038800	10.09
Bandhan Bank	170982500	88.43	ICICI Bank	117314400	10.39
RBL Bank	103412500	86.23	Siemens	1918500	10.77
India Cement	38123400	85.93	Torrent Phar	2160500	11.10

OI As on August 3,2018

कीमत में गिरावट के साथ ओपन इंटरेस्ट

	Open Int as on			Price as on		
	Mar 08	Mar 15	% Chg	Mar 08	Mar 15	% Chg
Apollo Tyres	11367900	15019500	32.1	516.7	473.0	-8.5
Dr Lal PathLabs	1502100	1977300	31.6	2179.1	2022.2	-7.2
Tata Chem	16497800	11334400	-31.3	1315.3	1128.8	-14.2
MRF	38905	50695	30.3	143956.7	141312.1	-1.8
NMDC	77521500	100129500	29.2	238.8	198.4	-16.9
SAIL	191048000	137040000	-28.3	139.0	121.7	-12.4
Bharat Elctn	143081400	182229000	27.4	215.2	188.9	-12.2
Page Inds	144300	182850	26.7	35870.7	34661.3	-3.4
Power Fin	68645625	85540625	24.6	429.8	381.0	-11.3
Maha Gas	4267200	3220800	-24.5	1316.0	1264.2	-3.9
Tata Steel	248264500	308874500	24.4	157.3	141.7	-9.9
Adani Ports	36877600	45601600	23.7	1325.5	1283.0	-3.2
DLF	32767350	39736950	21.3	920.3	823.7	-10.5
Canara Bank	43775100	53082000	21.3	598.0	549.2	-8.2
NTPC	85197000	101982000	19.7	352.2	316.3	-10.2
Power Grid	55548000	66207600	19.2	292.7	266.0	-9.1
Ipca Labs	2776800	2295150	-17.3	1187.6	1165.6	-1.8
Sun Pharma	16880500	14011200	-17.0	1605.7	1548.2	-3.6

बीएसई सूचकांक

	Mar 08	Mar 15	Change	% Chg
Sensex	**74119.4**	**72643.4**	**-1476.0**	**-2.0**
OUTPERFORM SENSEX				
TECk	16892.7	17026.2	133.5	0.8
IT	37744.2	37926.8	182.5	0.5
FMCG	19554.1	19384.4	-169.6	-0.9
UNDERPERFORM SENSEX				
PSU	19184.0	17555.3	-1628.7	-8.5
Metal	28737.2	26535.7	-2201.5	-7.7
Smallcap	44653.6	42012.8	-2640.8	-5.9
Oil & Gas	28466.2	26886.3	-1579.9	-5.5
Cap. Goods	59466.8	56820.1	-2646.7	-4.5
Auto	48387.9	46319.8	-2068.1	-4.3
Midcap	39852.9	38250.4	-1602.4	-4.0
Cons Durable	52673.4	50559.1	-2114.2	-4.0
BSE-500	32311.5	31360.7	-950.9	-2.9
Bankex	54394.4	52832.6	-1561.8	-2.9
Healthcare	34896.1	33910.4	-985.8	-2.8
Dollex-200	2042.8	1988.1	-54.7	-2.7
BSE-200	10158.4	9894.2	-264.3	-2.6
Dollex-100	2924.9	2854.0	-71.0	-2.4
BSE-100	23408.2	22857.9	-550.2	-2.4
Dollex-30	7350.1	7198.2	-151.9	-2.1

मार्केट एग्रीगेट्स

WEEK END			WEEK END		
BSE	Mar 08	Mar 15	NSE	Mar 08	Mar 15
Shares(In Lakhs)	31815	49011	Shares(In Lakhs)	160009	241624
Turnover(In Crore)	33780	62516	Turnover(In crore)	395707	590652
Traded(000)	15676	24011	Traded(000)	138264	216345

डिलिवरी

	BSE		NSE	
DATE	Trd. shares (bn)	% Delivery	Trd. shares (bn)	% Delivery
Mar 15, 2024	8047.6	51.7	51929.6	38.6
Mar 14, 2024	10526.8	51.8	51525.7	32.9
Mar 13, 2024	13734.8	68.0	54943.4	37.5
Mar 12, 2024	7879.6	58.1	35495.1	38.2
Mar 11, 2024	8845.5	60.3	33290.2	41.3
Mar 07, 2024	8012.3	53.8	33577.0	37.5
Mar 06, 2024	9818.6	64.5	45944.9	39.5
Mar 05, 2024	7223.7	61.8	35827.6	37.5
Mar 04, 2024	6766.9	62.3	34283.0	38.9

शेयर सूचकांकों में उतार चढ़ाव

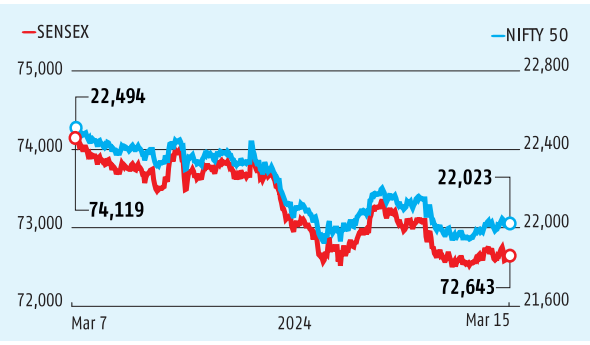

बीएसई 500

	Mar 07	Mar 15	% chg
मुनाफे में			
Solar Industries	7530.0	8860.6	17.7
Linde India	5579.1	6437.1	15.4
HEG	1698.7	1884.5	10.9
ZF Commercial	14320.7	15449.0	7.9
Poonawalla Fin	432.8	462.6	6.9
Relaxo Footwear	835.8	891.0	6.6
Colgate-Palmoliv	2579.0	2726.8	5.7
Narayana Hrudaya	1180.2	1242.5	5.3
Abbott India	27427.7	28423.3	3.6
Interglobe Aviat	3101.6	3203.4	3.3
Rail Vikas	238.0	245.8	3.3
Redington	204.8	211.5	3.2
Info Edg.(India)	5079.8	5241.7	3.2
Timken India	2597.4	2679.6	3.2
Cams Services	2901.4	2993.0	3.2
Cochin Shipyard	866.6	890.6	2.8
Trent	3951.3	4060.3	2.8
CG Power & Indu.	457.8	470.3	2.7
TCS	4110.1	4217.5	2.6
Intellect Design	1090.1	1118.3	2.6
CreditAcc. Gram.	1395.5	1430.6	2.5
Carborundum Uni.	1069.3	1095.8	2.5
United Breweries	1697.4	1738.9	2.4
360 ONE	678.8	695.3	2.4
Siemens	4668.5	4777.9	2.3
L&T Technology	5302.9	5417.9	2.2
SJVN	122.2	124.8	2.1
BLS Internat.	345.9	353.1	2.1
HDFC AMC	3743.0	3820.6	2.1
Ajanta Pharma	2082.5	2122.7	1.9
Nestle India	2559.9	2607.7	1.9
Britannia Inds.	4887.3	4976.3	1.8
Bharti Airtel	1199.2	1220.4	1.8
Oracle Fin.Serv.	8305.6	8448.8	1.7
Tube Investments	3500.1	3559.9	1.7
HDFC Life Insur.	621.8	632.2	1.7
Restaurant Brand	103.8	105.4	1.5
घाटे में			
Tata Inv.Corpn.	9744.4	7540.2	-22.6
Sobha	1520.4	1244.2	-18.2
NMDC	238.8	198.4	-16.9
Swan Energy	686.1	570.4	-16.9
Capri Global	248.2	207.4	-16.4
Natl. Aluminium	163.2	136.5	-16.4
Sterling & Wils.	584.0	488.5	-16.3
Engineers India	225.7	189.1	-16.2
B H E L	257.5	216.7	-15.8
Rites	737.8	622.6	-15.6
Jindal Worldwide	386.4	329.9	-14.6
Ramkrishna Forg.	724.2	619.0	-14.5
Macrotech Devel.	1171.9	1002.0	-14.5
Kaynes Tech	3110.5	2660.7	-14.5
Tata Chemicals	1314.9	1128.1	-14.2
JM Financial	87.9	75.5	-14.1
KIOCL	448.7	387.5	-13.6
Archean Chemical	688.0	595.2	-13.5
Sunteck Realty	457.2	396.3	-13.3
KNR Construct.	277.2	240.5	-13.2
Avanti Feeds	556.3	484.2	-13.0
IIFL Finance	420.4	366.9	-12.7
S A I L	139.0	121.8	-12.4
Data Pattern	2697.8	2363.2	-12.4
Bharat Electron	215.4	188.9	-12.3
RBL Bank	255.9	224.4	-12.3
Privi Speci.	1166.7	1024.9	-12.2
HFCL	102.5	90.1	-12.1
V I P Inds.	529.8	465.5	-12.1
Tata Tele. Mah.	89.9	79.0	-12.1
Shyam Metalics	640.5	563.1	-12.1
NBCC	127.3	112.0	-12.1
Prestige Estates	1183.4	1040.8	-12.1
Aegis Logistics	433.5	381.3	-12.0

सेक्टर सूचकांक

Return (%)	Mar 15	1 week	1 month	3 month	6 month	1 year
BSE Sensex	72,643.4	-2.0	0.8	1.6	7.1	26.2
S&P CNX Nifty	22,023.4	-2.1	0.5	2.6	9.1	29.8
BSE-100	22,857.9	-2.4	0.1	3.5	10.6	32.7
BSE-200	9,894.2	-2.6	-0.2	4.1	12.2	36.5
BSE-500	31,360.7	-2.9	-1.0	3.6	12.0	37.7
CNX Midcap	46,685.6	-4.7	-4.4	2.4	14.3	55.8
CNX Nifty Junior	58,058.8	-3.8	-0.2	11.7	26.1	55.4
S&P CNX 500	19,825.2	-3.0	-1.1	3.6	12.2	38.4
BSE-Auto	46,319.8	-4.3	0.7	12.6	24.6	63.5
BSE-Bankex	52,832.6	-2.9	0.6	-2.8	1.9	19.5
BSE-Cap. Goods	56,820.1	-4.5	2.9	4.3	20.8	65.4
BSE-Cons Durable	50,559.1	-4.0	0.8	4.1	9.3	36.0
BSE-FMCG	19,384.4	-0.9	0.8	-1.0	3.1	20.9
BSE-Healthcare	33,910.4	-2.8	-3.3	11.5	18.2	57.5
BSE-IT Sector	37,926.8	0.5	-1.8	4.3	13.3	33.1
BSE-TECk	17,026.2	0.8	0.1	6.3	13.3	31.3
BSE Realty	6,560.6	-9.3	-4.5	8.2	39.8	113.6
BSE-Metal	26,535.7	-7.7	-3.2	2.7	13.0	35.6
BSE-Oil & Gas	26,886.3	-5.5	-7.7	20.4	39.6	54.7
BSE-PSU	17,555.3	-8.5	-7.3	15.4	41.8	84.1

वैश्विक सूचकांक

Return (%)	Mar 15	1 week	1 month	3 month	6 month	1 year
FTSE 100	7,727.4	0.9	1.7	2.0	0.2	5.2
Nikkei 255	38,707.6	-2.5	1.4	17.4	15.4	42.2
Hang Seng	16,720.9	2.2	4.9	-0.4	-8.0	-14.4
Nasdaq	15,973.2	-0.7	0.4	7.8	16.5	39.7
Dow Jones	38,714.8	0.0	-0.2	3.8	11.8	21.5
Rs/$	82.9	-0.1	0.2	0.1	0.3	-0.3
Brent Crude (spot)$/Bbl	85.2	1.9	-0.1	10.6	-10.4	15.4

मोटा सौदा

Date	Stock	Client	Type	Quantity	Price (`)
Mar 13	ITC	Tobacco Manufacturers India	SELL	436851457	400.3
Mar 13	ITC	Icici Prudential Mutual Fund	BUY	124000000	400.3
Mar 13	ITC	Government Of Singapore	BUY	91545678	400.3
Mar 11	Interglobe Aviation	Rakesh Gangwal	SELL	7500000	3016.4
Mar 11	Interglobe Aviation	Rakesh Gangwal	SELL	7500000	3016.2
Mar 11	Interglobe Aviation	Rakesh Gangwal	SELL	7500000	3015.1
Mar 13	ITC	Capital Group/World	BUY	26581903	400.3
Mar 13	ITC	Bofa Securities Europe Sa	BUY	20400000	400.3
Mar 13	ITC	Societe Generale	BUY	18328425	400.3
Mar 13	ITC	Citigroup Global Markets Mauritius	BUY	17550000	400.3
Mar 11	Interglobe Aviation	Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.	BUY	2100000	3015.1
Mar 13	ITC	Morgan Stanley Asia Singapore Pte	BUY	15300000	400.3
Mar 12	Macrotech Developers	Sambhavnath Infrabuild And Farms	SELL	4972100	1180.0
Mar 13	ITC	Copthall Mauritius Investment	BUY	13570782	400.3
Mar 13	ITC	Monetary Authority Of Singapore	BUY	12004868	400.3
Mar 13	ITC	Ghisallo Master Fund Lp	BUY	11500000	400.3
Mar 13	APL Apollo Tubes	New World Fund Inc	BUY	2789398	1601.1
Mar 13	ITC	Marshall Wace Investment Strategies	BUY	9982861	400.3
Mar 15	Sundaram Finance	Vanguard Total International Stock Index Fund	BUY	912901	3796.5
Mar 15	Sundaram Finance	Vanguard Total International Stock Index Fund	BUY	885527	3796.5
Mar 13	ITC	New World Fund Inc	BUY	8271400	400.3
Mar 13	ITC	Nippon India Mutual Fund	BUY	8000000	400.3
Mar 13	ITC	Aditya Birla Sun Life Mutual Fund	BUY	6800000	400.3
Mar 13	ITC	Dsp Mutual Fund	BUY	6200000	400.3
Mar 15	Sundaram Finance	Ubs Principal Capital Asia	SELL	652968	3797.0
Mar 13	APL Apollo Tubes	Principal Global Investors Collective Investment Trust	SELL	1531367	1600.2
Mar 13	ITC	American Funds	BUY	5927528	400.3
Mar 13	ITC	Sbi Mutual Fund	BUY	5400000	400.3
Mar 12	Kfin Technologies	Kotak Mahindra Bank	SELL	3470000	600.3
Mar 14	Sundaram Clayton	Venu Srinivasan	SELL	1416247	1240.0
Mar 13	ITC	Tt Emerging Mkts Horizon Opportunities Fund	BUY	4070994	400.3
Mar 13	ITC	Mfs Fund	BUY	3809778	400.3
Mar 13	ITC	Max Life Insurance Company	BUY	3800000	400.3
Mar 13	ITC	Motilal Oswal Mutual Fund	BUY	3400000	400.3
Mar 13	ITC	Segantii India Mauritius	BUY	3115385	400.3
Mar 12	Nirlon	Nihar Nandan Nilekani	BUY	2252041	430.0
Mar 14	Sundaram Clayton	Sbi Mutual Fund	BUY	774000	1240.0
Mar 13	ITC	Goldman Sachs (Singapore) Pte	BUY	2250000	400.3

ओपन इंटरेस्ट ब्रेकअप

	Price as on Mar 15		Open interest		% of Open interest		
	Close (cash)	LTP (future)	Shares	` crore	Futures	Call	Put
Adani Enter	3132.2	3143.1	33891	10615.2	55.7	26.9	17.4
Adani Ports	1283.0	1289.1	74486	9556.6	61.2	23.3	15.4
Apollo Hosp	5983.2	6013.5	5077	3037.7	48.9	36.9	14.2
Asian Paints	2867.6	2878.4	14971	4293.0	51.9	32.7	15.4
Axis Bank	1046.4	1051.4	75648	7915.8	67.4	23.2	9.4
Bajaj Auto	8350.7	8355.8	6220	5194.0	40.3	42.8	16.9
Bajaj Fin	6514.4	6526.5	17036	11097.9	54.1	27.6	18.3
Bajaj Finsrv	1571.5	1578.8	15435	2425.5	66.3	21.7	12.0
Bharti Airtel	1220.0	1222.1	71166	8682.3	52.0	30.5	17.5
BPCL	586.5	587.0	77333	4535.2	38.2	42.5	19.4
Britannia	4974.2	4991.1	3378	1680.4	68.4	20.8	10.8
Cipla	1488.1	1490.9	15663	2330.7	64.4	21.2	14.4
Coal India	415.3	417.2	148686	6174.2	42.8	41.3	15.8
Divis Lab	3485.4	3502.4	5941	2070.6	65.4	24.8	9.8
Dr Reddys	6284.9	6307.8	3487	2191.4	59.2	27.4	13.3
Eicher Motor	3745.7	3757.2	6418	2404.1	56.3	32.0	11.7
Grasim Ind	2197.1	2198.3	10522	2311.8	71.1	23.6	5.2
HCL Techno	1647.3	1654.0	23631	3892.8	65.1	24.7	10.2
HDFC Bank	1452.7	1455.4	301449	43790.0	67.3	21.2	11.4
HDFC Std Life	632.4	634.5	44245	2797.9	59.1	27.0	13.9
Hero MotoCorp	4585.3	4585.5	7344	3367.6	55.6	32.1	12.4
Hindalco	532.6	533.5	67060	3571.3	59.1	27.0	13.8
HUL	2327.7	2338.8	23161	5391.1	60.7	26.4	12.9
ICICI Bank	1080.4	1080.8	117314	12674.1	71.3	18.2	10.4
IndusInd Bank	1484.4	1488.4	37148	5514.0	67.3	17.9	14.8
Infosys	1634.0	1640.9	49942	8160.5	60.7	27.3	12.0
ITC	419.1	420.9	295187	12371.3	43.0	39.6	17.4
JSW Steel	780.7	784.5	35728	2789.1	54.9	31.8	13.4
Kotak Mah Bank	1738.3	1742.6	54238	9428.3	70.7	18.2	11.1
L & T	3537.2	3554.7	25229	8923.9	63.4	25.6	11.0
LTIMindtree	5194.4	5215.8	4554	2365.3	61.1	27.5	11.4
Mah & Mah	1799.5	1807.4	28247	5083.0	53.6	33.1	13.2
Maruti Suzuki	11476.7	11493.1	5208	5976.8	52.1	32.9	14.9
Nestle India	2603.7	2615.1	6981	1817.6	72.8	19.3	8.0
NTPC	316.3	318.0	232371	7349.9	43.9	48.2	7.9
ONGC	258.8	260.1	214014	5537.6	43.8	43.4	12.8
Power Grid	266.0	267.0	140947	3748.5	47.0	38.3	14.7
Reliance Ind	2836.5	2849.9	77392	21951.9	54.9	33.0	12.0
SBI	731.9	734.5	215844	15797.6	46.3	35.8	17.9
SBI Life Ins	1500.0	1507.4	12651	1897.7	69.1	22.8	8.2
Sun Pharma	1548.2	1552.8	22039	3412.0	63.6	29.0	7.4
Tata Consumer P	1212.2	1215.1	20300	2460.7	50.3	29.9	19.8
Tata Motors	945.9	949.5	203976	19293.1	33.8	47.7	18.5
Tata Steel	141.7	142.3	703181	9964.1	43.9	39.8	16.2
TCS	4219.3	4239.8	23564	9942.4	58.6	23.5	17.9
Tech Mahindra	1282.2	1288.3	21784	2793.2	62.5	25.7	11.8
Titan Company	3633.2	3650.1	9303	3380.1	55.5	30.2	14.3
UltraTech	9633.0	9676.2	3646	3512.4	59.3	30.4	10.3
UPL	475.2	476.8	66516	3160.5	58.8	27.1	14.1
Wipro	517.0	518.0	104036	5378.6	48.8	36.0	15.3

परिवार की आय से सदस्यों का वेतन घटाएं और कर बचाएं

परिवार चुकाए गए होम लोन, बीमा प्रीमियम और कर बचत के लिए हुए दूसरे निवेश के जरिये भी कर सकते हैं आयकर लाभ का दावा

बिंदिशा सारंग

अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ) ऐसी कानूनी और वित्तीय व्यवस्था है, जो केवल भारत में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है ऐसे परिवार के सदस्यों से तो कर वसूला ही जाती है, पूरे परिवार से भी कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप आय को अविभाजित हिंदू परिवार की व्यवस्था में ले आते हैं तो आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य आय में कटौती और कर छूट का फायदा उठाकर आप पूरे परिवार का कर का बोझ बहुत कम कर सकते हैं।

सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर कुणाल सवानी कहते हैं, 'अविभाजित हिंदू परिवार अनूठी भारतीय संस्था है, जो बड़े संयुक्त परिवार के विचार पर आधारित होता है और हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से चलता है। चूंकि बतौर संस्था इससे कर वसूला जा सकता है, इसलिए ऐसे परिवार के लिए अलग से स्थायी लेखा संख्या पैन लेनी होती है और सदस्यों के आयकर रिटर्न के साथ-साथ पूरे परिवार का रिटर्न भी अलग से भरना पड़ता है।'

क्या है एचयूएफ

हिंदुओं के अलावा जैन, सिख या बौद्ध परिवार भी अविभाजित हिंदू परिवार बना सकते हैं। इस परिवार में एक ही पुरखे से आए सदस्य शामिल होते हैं। परिवार के सदस्य को कर्ता कहा जाता है। कर्ता पारिवारिक संपत्तियां संभालता है और एचयूएफ की ओर से वही सारे फैसले करता है।

एसकेवी लॉ ऑफिसेज में एसोसिएट आदित्य तिवारी बताते हैं, 'आयकर अधिनियम के तहत अविभाजित हिंदू परिवार कर छूट और लाभ का दावा कर सकता है और उसके सदस्य भी अलग से इन सभी का दावा कर सकते हैं।'

शिवदास ऐंड शिवदास लॉ चैंबर्स में वकील ऋषभ जे इसे ठीक से समझाते हैं। वह बताते हैं कि अविभाजित हिंदू परिवार की आय पर वित्त अधिनियम में दी गई स्लैब की दरों से या धारा 115बीएसी में दी गई नई कर प्रणाली के हिसाब से कर लगाया जाता है। वह कहते हैं कि कर तय करने और वसूलने के लिए एचयूएफ की नागरिकता की स्थिति तय करनी होती है।

कौन-कौन से कर लाभ

व्यक्तियों की तरह एचयूएफ को भी कई तरह की कर कटौती और छूट का फायदा मिल सकता है। सवानी बताते हैं, 'निजी करदाता कमाई कराने वाली अपनी पैतृक संपत्ति एचयूएफ को सौंपकर कर का बोझ कम कर सकते हैं। एचयूएफ को नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये और पुरानी व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ मिलता है।'

आयकर अधिनियम की धारा 80सी, 80डी और 80जी के तहत भी एचयूएफ करयोग्य आय में कटौती का पात्र होता है, जिससे परिवार का कर बोझ कम हो जाता है। सिंघानिया ऐंड कंपनी में प्राइवेट क्लाइंट लीडर केशव सिंघानिया समझाते हैं, 'यदि कोई व्यक्ति धारा 80सी के तहत कटौती का पूरा फायदा ले चुका है तो एचयूएफ के पास भी अपने सदस्यों की ओर से जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने और प्रीमियम चुकाने का विकल्प होता है, जिससे कर की और भी बचत हो जाती है।'

हिंदू अविभाजित परिवार आवास ऋण भी ले सकता है और चुकाए गए ब्याज तथा मूलधन पर धारा 24 और 80सी के तहत कर लाभ का दावा भी कर सकता है। तिवारी का कहना है, 'यह परिवार के हरेक सदस्य को आवास ऋण पर मिल रही कर कटौती के अलावा होता है। इससे परिवार की संपत्तियां संभालने और उनमें इजाफा करने में मदद मिलती है।'

कई बार लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि जैसे कुछ अनिवार्य अंशदान करने पड़ते हैं, जिनमें उनकी धारा 80सी की कर छूट सीमा खत्म हो जाती है। एक्विलॉ के कार्यकारी निदेशक राजर्षि दासगुप्ता की सलाह है, 'ऐसे में आप अपने एचयूएफ खाते से प्रीमियम देकर बदले में कर छूट का दावा कर सकते हैं।'

एचयूएफ अपने नाम एफडी खोलकर या इक्वटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) में निवेश कर कर छूट ले सकता है। अकॉर्ड ज्यूरिस एलएलपी में पार्टनर अलै रजवी कहते हैं, 'एचयूएफ लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता नहीं खोल सकते मगर अपने सदस्यों के पीपीएफ खातों में अंशदान कर धारा 80सी के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं।'

हिंदू अविभाजित परिवार अपने सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम चुकाकर धारा 80डी के तहत कर लाभ उठा सकता है। फिलहाल इस धारा के तहत सामान्य नागरिक 25,000 रुपये तक और वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपये तक कर योग्य आय घटवा सकते हैं। सभी सदस्यों की छूट सीमा इसी दायरे के तहत आती है। रजवी याद दिलाते हैं कि किसी एक निवेश या खर्च के लिए परिवार और सदस्य दोनों एक साथ छूट नहीं ले सकते।

सिंघानिया बताते हैं कि एचयूएफ योगदान करने वाले अपने सदस्यों को वेतन दे सकता है और उसे अपनी आय में से घटाकर कर योग्य आय कम कर सकता है। सवानी का कहना है कि इन छूटों और कटौतियों के जरिये हिंदू अविभाजित परिवार और उसके सदस्यों को निचले कर दायरे में बने रहने में मदद मिलती है। कई बार तो उनकी अतिरिक्त आय ऊपरी कर दायरे में नहीं आ पाती।

मगर ध्यान रखना होगा कि भारत से बाहर रहने वाले हिंदू अविभाजित परिवार को कर के मामले में अनिवासी माना जा सकता है। सावनी का कहना है कि ऐसे मामलों की जांच भी ज्यादा होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि एचयूएफ को ऊपर बताए कर लाभ हासिल करने के लिए पूरे कागजात साथ रखने चाहिए।

जोखिम से बचना है तो छोड़ दें स्मॉल कैप और मिड कैप फंड

संजय कुमार सिंह

पिछले एक साल में निफ्टी 50 करीब 27.4 फीसदी चढ़ा है जबकि निफ्टी मिड कैप 150 करीब 56 फीसदी और निफ्टी स्मॉल कैप 250 लगभग 66 फीसदी चढ़े हैं। इसी अवधि में मिडकैप और स्मॉलकैप फंडों में भारी निवेश देखा गया है। लेकिन इतनी तेज दौड़ के बाद अब इन फंडों में निवेशकों को पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मिडकैप फंडों के मुकालबे स्मॉलकैप फंडों में अधिक जोखिम रहता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत निवेश सलाहकार और सहजमनी के संस्थापक अभिषेक कुमार कहते हैं, 'स्मॉल कैप योजनाओं का बड़ा निवेश फ्री फ्लोट मार्केट कैप के मामले में शीर्ष 500 शेयरों के बाहर ही रहता है। इन अस्थिर शेयर में हाल के दिनों में ज्यादा तेजी देखी गई है।' स्मॉलकैप फंडों का लार्जकैप शेयरों में निवेश बहुत कम है। उनके पास इतनी नकदी भी नहीं होती कि बेचने या भुनाने के ज्यादा आवेदन ले पाएं।

इन फंडों में कई तरह के जोखिम होते हैं। सबसे पहला जोखिम तो मूल्यांकन का ही होती है। हालांकि स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों का मूल्यांकन अब बेहतर हो गया है। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के निदेशक-मैनेजर (रिसर्च) कौस्तुभ बेलापुरकर ने कहा, 'ऐसी लंबी दौड़ के बाद हमेशा ही गिरावट आती है, जैसी 2017-18 में देखी गई थी।'

लेकिन सूचकांक के स्तर पर फॉरवर्ड अर्निंग्स मल्टीपल उतना ज्यादा नहीं है, जितना 2018 में था। सैंक्टम वेल्थ की मुख्य निवेश अधिकारी और सह—प्रमुख ,उत्पाद एवं सॉल्यूशन रूपाली प्रभु कहती हैं, 'चुनौती तब शुरू होती है, जब आप वाजिब मूल्यांकन पर अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियां ढूंढने चलते हैं।'

धारणा या माहौल बदले तो नकदी का जोखिम भी हो सकता है। शेयरों के फ्री फ्लोट का बड़ा हिस्सा रखने वाले लार्ज फंडों के साथ खास तौर पर ऐसा हो सकता है। ज्यादा लोग बेचने आए तो फंड मैनेजर को परेशानी हो सकती है या शेयर के बारे में उसका नजरिया बदल सकता है। प्रभु समझाती हैं, 'असली खतरा तो इसके असर का है। फंड प्रबंधकों को कम कीमत पर शेयर बेचना पड़ सकता है, जिसका असर फंड के आगे के प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है।'

आमतौर पर फंड मैनेजर ब्लॉक डील या बल्क डील के जरिये शेयर बेचने की बात कहते हैं मगर प्रभु के मुताबिक चढ़ते बाजार में ऐसा करना आसान होती है किंतु बाजार लुढ़क रहा हो तो सौदे नहीं होते।

इतनी रकम आ रही हो तो फंड मैनेजर इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि पहले से खरीदे शेयर ही और खरीदें या नए शेयर जोड़ें। मौजूदा शेयर इतने तरल नहीं हैं कि और निवेश किया जाए तो मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में नए शेयर जोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रभु बताती हैं, 'इससे पोर्टफोलियो में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन इस बात की चिंता बढ़ जाती है कि फंड मैनेजर किसी भी शेयर उदाहरण के लिए 130वें स्थान पर मौजूद शेयर के बारे में गहरी समझ रखता है या नहीं।'

निवेशकों की उम्मीदें हालिया रिटर्न से जुड़ी हैं। कई निवेशकों को उम्मीद है कि हर साल ऐसा ही रिटर्न मिलता रहेगा। बेलापुरकर के हिसाब से निवेशक इससे अलग-अलग उप-परिसंपत्ति और परिसंपत्ति श्रेणियों में जाने के बजाय स्मॉल और मिडकैप फंडों में अधिक निवेश कर सकते हैं।'

साल 2018 की तरह जब धारणा एकदम उलट जाती है तो कई निवेशक बाहर निकलना चाहते हैं। उनकी अर्जी निपटाने के लिए फंड हाउस फरमाइश के हिसाब से शेयर बेच देते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले अधिक तरल शेयर ही पहले बिकते हैं। इसके बाद पोर्टफोलियो में कम गुणवत्ता और तरलता वाले शेयर ही बचते हैं। ऐसे में नुकसान लंबी अवधि के निवेशकों को होता है। सेबी फंड कंपनियों से दीर्घावधि निवेशकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता ढांचा तैयार करने के लिए कह रहा है।

ऐसे में आप क्या करें? निश्चित आमदनी वाली योजनाओं में पर्याप्त निवेश रखें। कुमार कहते हैं कि अचानक मंदी आने पर स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में उठापटक आए तो घाटा झेलकर उन्हें न बेचें। वह मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में उतनी ही रकम रखने के लिए कहते हैं जो अगले 5 से 10 वर्षों तक लगी रह सके।

जो लोग भारी गिरावट (40 फीसदी तक) बरदाश्त नहीं कर सकते उन्हें पूरी तरह से बाहर निकल जाना चाहिए। जिनके पास दोनों फंड हैं वे अपने परिसंपत्ति आवंटन पर टिके रह सकते हैं। बेलापुरकर कहते हैं, 'अगर आप इन श्रेणियों में ओवरवेट हो गए हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो पुनर्संतुलित करना चाहिए।' इस वक्त एकमुश्त निवेश से बचें और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) पर टिके रहें। बेलापुरकर कहते हैं, 'अगर आप इन श्रेणियों में ओवरवेट हो गए हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो पुनर्संतुलित करना चाहिए।' इस वक्त एकमुश्त निवेश से बचें और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) पर टिके रहें।

व्यापार गोष्ठी | विषय: निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय होने का क्या होगा असर ?

निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगे अंकुश पर बनी रहे उनकी सेहत

निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक

निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय होने से आम जनता को काफी सहूलियत होगी। इलाज शुरू करने से पहले ही मरीज एवं उनके परिजनों को अस्पताल के शुल्क संबंधी नियम मालूम होने चाहिए। इससे अस्पतालों की मनमानी पर रोक लग सकेगी। इलाज की दरों में एकरूपता होनी चाहिए। सरकार को निजी अस्पतालों के लिए ओपीडी, सर्जरी के स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी करने चाहिए।

ललित महालकरी
इंदौर, मध्य प्रदेश

आम लोगों की बनेगी पहुंच

निजी अस्पतालों में इलाज की दरें निर्धारित होने से न केवल स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति के मौलिक अधिकार को बल मिलेगा अपितु आम लोगों की भी पहुंच निजी अस्पतालों तक बनेगी। लेकिन विडंबना है कि इन दिनों निजी अस्पताल लूट, मनमानी और बदसलूकी की घटनाओं का अड्डा बनते जा रहे हैं। इसकी वजह शुल्क निर्धारण में व्याप्त व्यापक असमानता है।

डॉ. हर्ष वर्द्धन कुमार
पटना, बिहार

तय हों इलाज की दरें

निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय होना बेहद जरूरी है क्योंकि इन अस्पतालों में इलाज आम लोगों की जेब से बाहर है। जिस तरह से सरकारी अस्पताल में हर इलाज की एक निश्चित राशि तय की गई है उसी तरह से यहां भी यह बेहद जरूरी है। सरकार निजी अस्पतालों में भी हर तरह के इलाज के लिए एक निश्चित राशि तय करें। अधिक पैसा लेने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हो।

मनमोहन राजावत
शाजापुर, मध्य प्रदेश

सस्ती दरों पर मिलेगा अच्छा इलाज

अभी भी बहुत से निजी बड़े और महंगे अस्पताल सीजीएचएस दरों या पीएसयू आदि की मानक दरों पर इलाज की सुविधा दे रहे हैं, जबकि ये दरें इनकी अपनी दरों से बहुत कम हैं। निजी अस्पताल सीजीएचएस या पीएसयू के पैनल पर अपनी मर्जी से आते हैं। मतलब साफ है निजी अस्पताल कम या मानक दरों पर भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं दे सकते हैं।

बृजेश माथुर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

मनमानी वसूली पर लगेगा अंकुश

नए नियम से निजी अस्पतालों की इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगेगा। निगरानी तंत्र सुनिश्चित करें कि इसका सख्ती से पालन हो। मरीज अधिक सुविधायुक्त निजी अस्पतालों की ओर रुख करेंगे। जिससे सरकारी तंत्र पर कार्य का दबाव कम होगा और स्वास्थ्य बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सुविधा की गुणवत्ता बढ़ेगी।

मोहित सोनी
धार, मध्य प्रदेश

मध्यम और गरीब लोगों को फायदा

सरकारी अस्पतालों में लचर व्यवस्था होने से लोग निजी अस्पताल में इलाज कराते हैं। लेकिन देश की आधी आबादी निजी अस्पताल में इलाज कराने में समर्थ नहीं है। इसलिए निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय होने से मध्यम व गरीब लोगों को फायदा होगा और इससे इस वर्ग के लोगों की जान भी बच सकती है क्योंकि बहुत से गरीब वर्ग के लोग महंगे इलाज के कारण दम तोड़ देते हैं।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

मरीजों को किफायती इलाज

निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय होने से मरीज और उनके परिजन लुटने से बच सकेंगे। सरकारी अस्पतालों पर बोझ भी कम होगा। हालांकि यह तभी सफल होगा जब सरकार शिकायत मिलने पर कठोर कदम उठाएगी। दरें तय होने का निजी अस्पतालों पर प्रतिकूल असर हो सकता है क्योंकि सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा निजी अस्पतालों में महंगी सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है।

शकुंतला महेश नेनावा
इंदौर, मध्य प्रदेश

सरकारी अस्पतालों का बोझ कम होगा

अगर निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय हो जाती है तो इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। निजी क्षेत्र में नए अस्पताल बढ़ेंगे जिससे सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम पड़ेगा। भारत में जब सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित हैं तो इलाज की दरें भी निर्धारित होनी चाहिए। इलाज की दरें अस्पताल के स्तर, जनसंख्या तथा जगह के अनुरूप निर्धारित होनी चाहिए।

रवीन्द्र जोशी
अंबाला, हरियाणा

इलाज में लूट से मिलेगी मुक्ति

निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय होने से आम व्यक्ति के साथ इलाज के नाम पर होने वाली लूट पर रोक लगेगी। आमतौर पर निजी अस्पतालों में मरीज की बीमारी के नाम पर वास्तविकता से ज्यादा पैसा परिवार वालों से लिया जाता है, जबकि उतना पैसा उस बीमारी पर लगता ही नहीं है। निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय होने से इस बात की पारदर्शिता बनी रहेगी कि इस बीमारी पर इतना पैसा लगेगा।

आशीष सकलेचा
रतलाम, मध्य प्रदेश

बजट के अनुसार इलाज संभव

निजी अस्पतालों में इलाज की दरें निर्धारित होने पर रोगी की चिकित्सा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रह सकती है। रोगी व उसके परिजन अपनी आर्थिक क्षमता और बजट के अनुसार चिकित्सा के आवश्यक सोपानों का प्राथमिकता से निर्धारण कर सकते हैं। चिकित्सा की दरें निर्धारित होने पर निजी अस्पतालों की आपसी प्रतिस्पर्धा कम होगी। जिसका लाभ निम्न और मध्यम वर्ग के साथ आम जनता को मिलेगा।

हार्दिक जैन
इंदौर, मध्य प्रदेश

निजी अस्पतालों में सेवा नहीं लूट मची है

निजी अस्पतालों में डॉक्टरों का शुल्क, अनावश्यक जांच का भारी भरकम खर्च और कमरों का शुल्क सामान्य आदमी की सीमा से बाहर है। सरकार द्वारा सिर्फ निजी अस्पतालों की इलाज की दरें तय कर देने से बात नहीं बनेगी। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की फीस, चिकित्सा शिक्षा का खर्च और दवा निर्माताओं द्वारा खुली लूट रोकने जैसे अन्य प्रभावी उपाय करने होंगे।

निर्मल कुमार पाटोदी
इंदौर, मध्य प्रदेश

आम जन के हिसाब से तय हों दरें

निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय होने से आम जन को फायदा मिलेगा। गंभीर बीमारियों पर ज्यादा खर्च आता है। इलाज खर्च अस्पतालों के स्टैंडर्ड के हिसाब से तय होता है। जितना बड़ा अस्पताल होगा इलाज उतना महंगा होगा। समर्थ तो महंगा इलाज करा सकता है लेकिन आम जन नहीं करा सकता है, उसे मजबूरी में कराना पड़ता है। इलाज की दरें जनहित को देखते हुए तय होनी चाहिए।

शेर सिंह मेरूपा
लाहुल, हिमाचल

बकौल विश्लेषक

निजी अस्पतालों को होगी परेशानी

निजी अस्पतालों में सरकारी दर पर इलाज करना मुनासिब नहीं होगा। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर ऐसा कोई फैसला देता है तो फिर इसे लागू करना चाहिए मगर मेरे ख्याल से यह वास्तव में हो नहीं पाएगा। इसके कई कारण हैं, पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कारण तो यही है कि सरकारी अस्पतालों में बेड, चिकित्सा उपकरण, शल्य चिकित्सा उपकरण आदि सरकार देती है, जबकि निजी अस्पताल संचालकों को सब कुछ खुद के खर्च से करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों के लिए जमीन, बुनियादी ढांचा आदि सरकारी विभाग करते हैं, लेकिन निजी अस्पतालों को जमीन खरीदनी पड़ती है या फिर वे लीज पर लेकर अपना अस्पताल चलाते हैं। इससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों का वेतन, भत्ता आदि सरकार की ओर से दिया जाता है, लेकिन निजी अस्पताल अपनी कमाई से ही अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करते हैं। इन सभी मसलों पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे निजी अस्पतालों के संचालन में परेशानी आ सकती है।

बातचीत: अभिषेक मिश्र

डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह
पूर्व अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश

सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज के खर्च में बड़ा अंतर है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब इन दरों का नियमन होने की उम्मीद है। जिससे निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से की जा रही लूट पर लगाम लगेगी और उन्हें सस्ता इलाज मिलेगा। मानक उपचार दिशा निर्देश भी लागू करने की जरूरत है क्योंकि अभी इसके अभाव में मरीज को जिस उपचार की जरूरत नहीं है, वह भी उसे दिया जाता है। जिससे मरीज का इलाज खर्च बढ़ जाता है। निजी अस्पतालों के लिए इलाज की दरें आयुष्मान भारत या केंद्र सरकार की सीजीएचएस योजना की दरों के आधार पर तय हो। जहां तक निजी अस्पतालों के दरें तय करने से गुणवत्ता प्रभावित होने का सवाल है तो इलाज की गुणवत्ता गलत इलाज करने से प्रभावित होती ना कि दवा या जांच के दाम से। अस्पताल में कमरे का किराया आदि की दर तय करने की छूट दी जा सकती है।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

अमूल्य निधि
राष्ट्रीय सह संयोजक, जन स्वास्थ्य अभियान

पुरस्कृत पत्र

1

डॉ. उमेश मित्तल
सहारनपुर, उत्तर

पुरस्कार राशि
500 रुपये

निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च में पारदर्शिता हो

इसमें कोई संदेह नहीं है कि समझदार लोग प्रायः निजी अस्पतालों में इलाज कराने को प्राथमिकता देते हैं। इसके कारणों में सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था, उचित देखभाल की कमी और डॉक्टरों का विशेषज्ञ न होना शामिल है। जबकि निजी अस्पतालों में तुरंत इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा होना है। इसलिए निजी अस्पतालों में फीस भी ज्यादा लगती है। फिर भी निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च में पारदर्शिता और कुछ कमी होनी चाहिए।

श्रेष्ठ पत्र

रमेश चंद्र कर्नावट
उज्जैन, मध्य प्रदेश

उचित खर्च पर बेहतर इलाज

सरकारी अस्पतालों की तुलना में बेहतर चिकित्सा का दावा करने वाले निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मनमानी राशि वसूल करते आए हैं। कुछ निजी अस्पतालों के इलाज का खर्च मध्यमवर्गीय परिवार की पहुंच से बाहर है। इलाज की दरें तय हो जाने पर अपेक्षाकृत उचित खर्च पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय होने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा।

मनोज पालीवाल
रायपुर, छत्तीसगढ़

बेहतरीन सेवाएं मिले

निजी क्षेत्र के अस्पतालों के लिए सरकार को कोई दरें तय नहीं करनी चाहिए। किसी भी सामान और सेवा की दर खुले बाजार से तय होना चाहिए। जो अच्छी सेवा देगा और दरें बेहतर होंगी तो लोग अपने आप इलाज कराएंगे। लेकिन उसे नियमों में बांधकर हम उसकी प्रगति को रोक देंगे। अगर निजी क्षेत्र इलाज का उचित पैसा नहीं लेगा और सरकारी दरों पर ही चिकित्सा देगा तो वह भी सरकारी अस्पतालों की तरह बीमार हो जाएगा।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

उद्योग के लिए नुकसान

निजी अस्पतालों का कहना है कि यह कदम उद्योग के लिए विनाशकारी साबित होगा। उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में लागत अधिक है। इसलिए यूपी और दिल्ली में दरें एक जैसी नहीं हो सकती हैं। निजी अस्पतालों की दलील है कि हरेक अस्पताल में लागत ढांचा अलग-अलग है और यह भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करता है। बड़े अस्पताल और छोटे क्लीनिक के लिए एक जैसी लागत प्रणाली लागू नहीं की जा सकती है।

...और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी में आपके विचारों को प्रकाशित करते हैं। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -

चुनावी बॉन्ड: गोपनीयता बनाम पारदर्शिता पर आपकी राय ?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201

या फिर ई-मेल करें

goshthi@bsmail.in

भाजपा अव्वल, विपक्ष भी पीछे नहीं

चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6,986.5 करोड़ और दूसरे नंबर पर रही तृणमूल को मिले 1,397 करोड़ रु

अब रद्द हो चुके चुनावी बॉन्ड के शीर्ष खरीदार 'फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज' ने इसके माध्यम से तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक को 509 करोड़ रुपये का दान दिया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से रविवार को यह जानकारी सामने आई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) द्वारा बताए गए 656.5 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड से मिली कुल रकम में 'फ्यूचर गेमिंग' द्वारा दिया गया दान 77 प्रतिशत से अधिक है। इस कंपनी के मालिक, 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं।

अधिकांश राजनीतिक दलों ने दानदाताओं के नामों का खुलासा नहीं किया है। इसलिए यह ज्ञात नहीं है कि 'फ्यूचर गेमिंग' द्वारा खरीदे गए शेष 859 करोड़ रुपये के बॉन्ड के लाभार्थी कौन थे। यह खुलासा उच्चतम न्यायालय के आदेश पर निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए कुल 523 मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित आंकड़ों के विवरण का हिस्सा है। पिछले सप्ताह निर्वाचन आयोग द्वारा एक और आंकड़ा प्रकाशित किया गया था, जो भारतीय स्टेट बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर आधारित था।

भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खुलासों की स्कैन की गई प्रतियां शामिल हैं। यह प्रतियां सैकड़ों पृष्ठों में हैं। शुरुआत में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा 12 अप्रैल, 2019 से पिछले महीने शीर्ष अदालत द्वारा बॉन्ड को खत्म करने तक की अवधि से संबंधित था, वहीं नवीनतम खुलासा पिछले साल नवंबर में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 2018 की शुरुआत में योजना शुरू होने के बाद से उनके द्वारा भुनाए गए बॉन्ड पर दी गई घोषणाओं पर आधारित है और इसमें अंतिम कुछ किस्तों को शामिल नहीं किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना के लागू होने के बाद से इनके (बॉन्ड के) माध्यम से सबसे अधिक 6,986.5 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (1,397 करोड़ रुपये), कांग्रेस (1,334 करोड़ रुपये) और भारत राष्ट्र समिति (1,322 करोड़ रुपये) का स्थान रहा।

आंकड़ों के मुताबिक, ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजद को 944.5 करोड़ रुपये मिले। इसके बाद द्रमुक ने 656.5 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने लगभग 442.8 करोड़ रुपये के बॉन्ड भुनाए। गैर सरकारी संगठन, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे गए थे। दोनों आंकड़ों को मिलाकर अनुमान लगाया गया है कि योजना की पूरी अवधि के दौरान भाजपा को कुल 7,700 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनता दल (सेक्युलर) को 89.75 करोड़ रुपये के बॉन्ड मिले, जिसमें चुनावी बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार मेघा इंजीनियरिंग से मिले 50 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

फ्यूचर गेमिंग कंपनी 1,368 करोड़ रुपयों के साथ चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार थी, जिसमें से लगभग 37 प्रतिशत द्रमुक को गया। द्रमुक के अन्य प्रमुख दानदाताओं में मेघा इंजीनियरिंग 105 करोड़ रुपये, इंडिया सीमेंट्स 14 करोड़ रुपये और सन टीवी 100 करोड़ रुपये शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 1,397 करोड़ रुपये मिले और वह भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता है। द्रमुक दानदाताओं की पहचान का खुलासा करने वाले कुछ राजनीतिक दलों में से एक है, जबकि भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल और आप जैसे प्रमुख दलों ने निर्वाचन आयोग को इन विवरणों का खुलासा नहीं किया था।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अब सार्वजनिक कर दी है। तेदेपा ने 181.35 करोड़ रुपये, शिवसेना ने 60.4 करोड़ रुपये, राजद ने 56 करोड़ रुपये, समाजवादी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 14.05 करोड़ रुपये प्राप्त किए। आंकड़ों में कहा गया कि अकाली दल ने 7.26 करोड़ रुपये, अन्नाद्रमुक ने 6.05 करोड़ रुपये, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारती ग्रुप से मिले 50 लाख रुपये के बॉन्ड भुनाए। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को भी 50 लाख रुपये के चुनावी बॉन्ड दान में मिले।

आम आदमी पार्टी ने हालांकि अपने दान का संचयी आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चला कि उसे 65.45 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि निर्वाचन आयोग में दी गई जानकारी के बाद उसे 3.55 करोड़ रुपये और मिलने का अनुमान है, जिससे कुल दान 69 करोड़ रुपये हो गया। माकपा ने घोषणा की थी कि वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त नहीं करेगी, जबकि एआईएमआईएम, इनेलोद और बसपा ने कोई रकम प्राप्त नहीं करने की जानकारी दी है। खुलासे के बाद, विपक्षी दलों ने चुनावी बॉन्ड को वैध भ्रष्टाचार करार दिया है, जबकि भाजपा ने कहा है कि बांड को खत्म करने से राजनीति में काले धन की वापसी हो सकती है।

भाषा

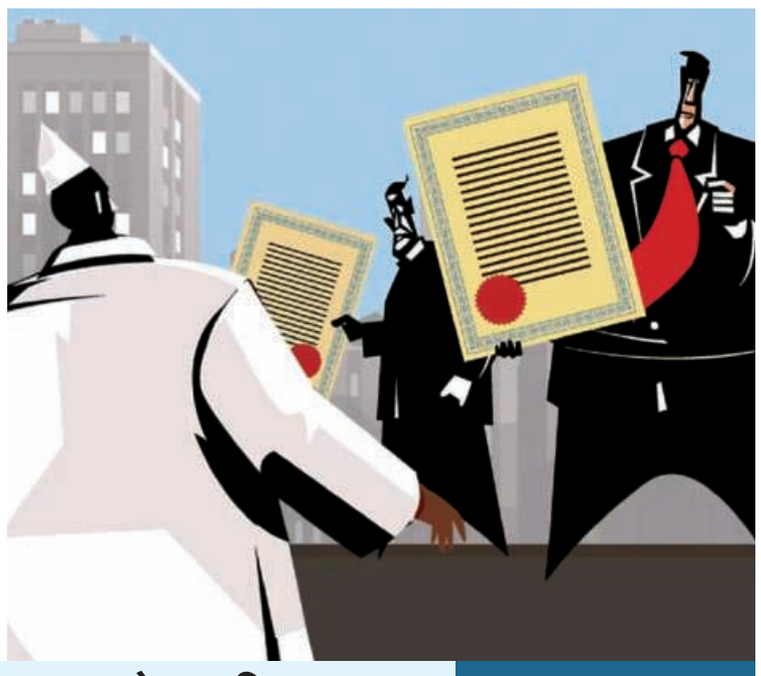

द्रमुक को बड़ा हिस्सा

- फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज रही चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार, इसका बड़ा हिस्सा द्रमुक को मिला
- चुनावी बॉन्ड से बड़ी रकम पाने वालों में कांग्रेस (1,334 करोड़ रुपये) और भारत राष्ट्र समिति (1,322 करोड़ रुपये) का स्थान
- एआईएमआईएम, इनेलोद और बसपा ने चुनावी बॉन्ड से कोई रकम प्राप्त नहीं करने की जानकारी दी
- भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चला कि आप को 65.45 करोड़ रुपये मिले

बुलेट ट्रेन पर सवार होगा भाजपा का चुनाव अभियान

ध्रुवाक्ष साहा

लोक सभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार अभियान बुलेट ट्रेन के साथ आगे बढ़ेगा। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में मतदाताओं से अगले पांच वर्षों के दौरान देश में कई और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शुरू करने का वादा कर सकती है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'पिछले चुनाव में किए गए वादों पर काम जारी रखते हुए पार्टी अगले पांच वर्षों के लिए हाई स्पीड रेल की कई परियोजनाओं को अपने मुख्य मुद्दों में शामिल करने पर विचार कर रही है। ये परियोजनाएं चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकती हैं।' वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने कहा था कि वह देश में हाई स्पीड ट्रेन का जाल फैलाएगी। यह बात उसके घोषणा पत्र में भी शामिल थी। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता को भेजे गए सवालों का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिला था।

पिछले आम चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में कहा गया था, 'हम अगले पांच वर्षों में हाई स्पीड रेल संपर्क का विस्तार करेंगे और देशभर में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनें शुरू करेंगे।' अपने घोषणा पत्र के अनुसार चुनावी वादों को अमलीजामा पहनाते हुए भाजपा सरकार ने प्रमुख मार्गों पर बुलेट ट्रेन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराया और कई कॉरिडोर पर आकलन भी पूरा करा लिया है।

मौजूदा समय में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर गुजरात के सूरत और बिलिमोड़ा के बीच 2026 तक परिचालन शुरू होने की संभावना है। पूरे कॉरिडोर के 2028 तक शुरू हो जाने की संभावना है। मालूम हो कि इस परियोजना के चालू होने की तारीख 2022 रखी गई थी।

वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि देश भर में बुलेट ट्रेन के 7 कॉरिडोर शुरू करने पर विचार चल रहा है। इनमें दिल्ली-वाराणसी (813 किमी), दिल्ली-अहमदाबाद (878 किमी), मुंबई-नागपुर (765 किमी), मुंबई-हैदराबाद (671 किमी), चेन्नई-बेंगलूरु-मैसूर (435 किमी), दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर (459 किमी) और वाराणसी-हावड़ा (760 किमी) रूट शामिल हैं। इन सातों कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी अध्ययन और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जैसे शुरुआती तैयारी के काम तेजी से कराए गए। किसी भी परियोजना की लागत और रूट पर बुनियादी ढांचा वगैरह का आकलन करने के लिए ये प्राथमिक और सबसे जरूरी कार्य होते हैं।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए वास्तविक लागत पर आईआरआर (इंटरनल रेट ऑफ रिर्टन) लगभग 12 प्रतिशत आंका गया। हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि परियोजना पूरी होने की वास्तविक समयसीमा 2022 से छह साल की देरी होने के चलते इसकी लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है।

एक और सूत्र ने बताया कि सात कॉरिडोर में से इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में 2 या 3 बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इनकी फिजिबिलिटी और डीपीआर रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है और मंत्रालय ने इनका आकलन भी किया है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने पिछले साल अक्टूबर में लिखा था कि जेवर में एयरपोर्ट तैयार होने के मद्देनजर अन्य शहरों तक आवाजाही आसान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर की मांग की जा रही है।

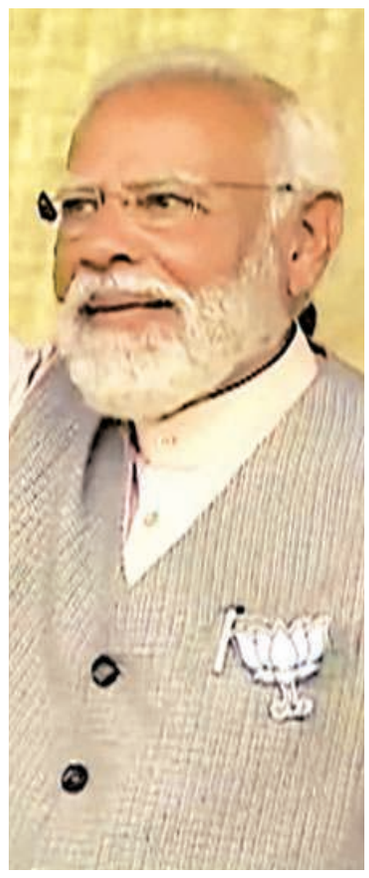

नई सरकार के 100 दिन की रूपरेखा बनाएं मंत्री : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों से नई सरकार के पहले 100 दिनों और अगले पांच साल के लिए एक रूपरेखा तैयार करने को कहा। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा कि नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले पांच साल के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। यह बैठक निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद हुई है।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचन आयोग की सिफारिश भेजकर सात चरण के संसदीय चुनावों की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू की। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 102 सीट पर मतदान के लिए पहली अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही किसी विशेष चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

छोटी कंपनियों ने अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा चंदे में दिया

सचिन मामपट्टा

छोटी कंपनियों ने बड़ी कंपनियों की तुलना में अपने शुद्ध मुनाफे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड के रूप में राजनीतिक दलों को चंदा दिया है।

देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों ने पिछले चार वर्षों में अपने कुल मुनाफे का महज 0.2 फीसदी के बराबर ही चंदा दिया है, जबकि, 10 सबसे कम मूल्यवान कंपनियों ने 14.8 फीसदी दान किया। यह जानकारी उन 95 सूचीबद्ध कंपनियों के आंकड़ों पर आधारित है जिनके बारे में भारतीय स्टेट बैंक के खुलासे से जानकारी मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की है। हालांकि, यह संख्या व्यापक नहीं है, लेकिन इससे बड़ी कंपनियों के व्यापक रुझान का संकेत तो मिलता ही है।

बाजार मूल्यांकन के हिसाब से 10 बड़ी कंपनियों ने करीब 362 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। पिछले चार वर्षों में इनका मुनाफा 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। वहीं बाजार मूल्यांकन के हिसाब 10 छोटी कंपनियों ने राजनीतिक दलों को 125 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। इन चार वर्षों में उनका लाभ सिर्फ 844.5 करोड़ रुपये रहा।

कई कंपनियों ने तो पिछले चार वर्षों के दौरान अपने मुनाफे से अधिक का चंदा दे दिया है। ऐसी 10 कंपनियां हैं जिन्होंने चार वर्षों के दौरान कमाए शुद्ध लाभ से अधिक राजनीतिक दलों को चंदा दे दिया है। इन कंपनियों के वित्तीय आकंड़ों से यह जानकारी मिली है। इन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल मिलाकर 240 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा दिया।

करीब 4 कंपनियों ने बीते 5 वर्षों के अपने मुनाफे का 5 फीसदी के बराबर या उससे ज्यादा रकम राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दीं। दो कंपनियों के मामले में यह दो अंकों में था, जबकि एक कंपनी ने शुद्ध लाभ का 52 फीसदी हिस्सा राजनीतिक दलों को दान कर दिया।

बाजार मूल्यांकन के हिसाब से निचले स्तर की आधी कंपनियों की हिस्सेदारी उन कंपनियों की तुलना में दोगुनी थी, जिन्होंने बीते चार वर्षों के दौरान अपने कमाए हुए लाभ से ज्यादा दान दिया था।

कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड को 'दान, विविध खर्चों' में दर्शाया

कृष्णकांत

कोई तय ढांचा नहीं होने के कारण कई बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड की खरीद और राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे के बारे में अपनी सालाना रिपोर्ट में अलग-अलग प्रारूप में बताया है। इन आंकड़ों को विविध खर्चों और दान के तहत दिखाया गया है, हालांकि इसमें उल्लेख किया गया है कि यह राशि चुनावी बॉन्ड की खरीद अथवा राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दी गई है।

इन रिपोर्टों के अध्ययन से पता चलता है कि राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे को दर्शाने के लिए कोई मानक तरीका नहीं है और इसे कंपनी पर ही छोड़ दिया गया है कि वे इसे बताएं अथवा न बताएं। कई कंपनियों ने बगैर किसी विवरण के सभी चंदों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जबकि कई बड़े खरीदारों ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बॉन्ड का कोई उल्लेख तक नहीं किया है। कंपनियों की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में खनन और धातु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांत ने चुनावी बॉन्ड पर सर्वाधिक खर्च किया। उसके बाद भारती एयरटेल और जिंदल स्टील ऐंड पावर का स्थान रहा। वेदांत ने वित्त वर्ष 2023 में 155 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड की खरीद की। उससे पहले वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 123 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे थे।

वित्त वर्ष 2023 में चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली या राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली अन्य बड़ी कंपनियों में महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (25 करोड़ रुपये), सिप्ला (24.2 करोड़ रुपये), टॉरंट पावर (23 करोड़ रुपये), अरविंद फार्मा (21.5 करोड़ रुपये), मारुति सुजुकी (20 करोड़ रुपये) और हीरो मोटोकॉर्प (20 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

उड़न दस्ते और नियंत्रण कक्ष बने

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं को डराने-धमकाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शहर के सात लोकसभा क्षेत्रों में उड़न दस्ते और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने रविवार को सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी। **भाषा**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda Hamesha Aapke Liye
www.bankofbaroda.in

TENDER NOTICE

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	निविदा का नाम	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	ग्राहकों से इन्स्ट्रूमेंट्स प्राप्त करने तथा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के तहत इनकी प्रोसेसिंग के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध।	08.04.2024
2	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ग्राहकों से कैश पिकअप सुविधा के लिए सम्पूर्ण भारत में एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध जिसमें डेटा एंट्री और डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के तहत जमा पर्ची (प्रोसेसिंग सेवाओं हेतु) की इमेज कैप्चर करना शामिल है।	08.04.2024

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड पर उपलब्ध है।
'अन्य सूचना', यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट पर **www.bankofbaroda.in** निविदा खंड में जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें ।

स्थान: मुंबई
दिनांक : 18.03.2024 **महाप्रबंधक (बीसीएमएस एवं एससीएफ)**

148/23-24

आजादी के बाद दूसरा सबसे लंबा चुनाव कार्यक्रम

निर्वाचन आयोग ने लोक सभा चुनाव की रणभेरी बजा दी है। शनिवार 16 मार्च को घोषित कार्यक्रम के अनुसार सात चरणों में होने वाली चुनाव की प्रक्रिया 81 दिन में पूरी होगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और अंतिम चरण का 1 जून को होगा। वर्ष 1951-52 के बाद यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनावी कार्यक्रम है। उस समय पूरी चुनावी प्रक्रिया चार महीने तक चली थी। इस बार का चुनाव कार्यक्रम 2019 के चुनाव से भी छह दिन लंबा है, जो 75 दिन में समाप्त हुआ था। निर्वाचन आयोग ने 2019 के लोक सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को किया था। पिछला लोक सभा चुनाव भी सात चरणों में हुआ था और मतगणना 23 मई को हुई थी। उससे पहले वर्ष 2014 में 5 मार्च को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और 16 मई को मतगणना तक पूरी प्रक्रिया 73 दिनों में संपन्न हुई थी।

निर्वाचन आयोग के अनुसार 2024 में पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर और चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर तो छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर मतदान होगा। अंतिम चरण में 1 जून को 57 सीटों पर लोग मताधिकार के जरिए जनप्रतिनिधि चुनेंगे।

पिछले लोक सभा चुनाव में 67.4 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले थे। इससे पहले के चुनाव यानी 2014 में थोड़ा कम 66.44 फीसदी मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले के चुनाव 2009 में यह केवल 58.21 फीसदी ही था। यूं तो मतदान प्रतिशत पिछले तीन चुनाव से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता। इस बार मतदान प्रतिशत और बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने 'एक मतदाता भी छूट न जाए' नाम से अभियान शुरू किया है।

बढ़े 5 करोड़ मतदाता

पिछले लोक सभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में लगभग पांच करोड़ का इजाफा हुआ है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2024 को देश में 96.88 करोड़ मतदाता हैं। वर्ष 2019 में 91.19 करोड़ और 2014 में 83.4 करोड़ मतदाता थे। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या 47.1 करोड़ या 48.61 फीसदी है, जबकि पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 48.09 फीसदी था। इसके अलावा 18-19 आयु वर्ग के 1.84 करोड़ अथवा 1.89 फीसदी मतदाता हैं। वर्ष 2019 में यह संख्या 1.5 करोड़ या कुल मतदाताओं का 1.64 फीसदी थी। यही नहीं, इस वर्ष 18 से 29 आयु वर्ग के 21.58 करोड़ मतदाता हैं जो कुल मतदाताओं का 22.27 फीसदी है। पिछले चुनाव के दौरान यानी 2019 में इस वर्ग में मतदाताओं की संख्या 25.37 फीसदी थी। इस बार 48,044 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। पिछले चुनाव में इनकी संख्या 39,075 थी।

प्रति 1000 पुरुष पर 948 महिला मतदाता

लिंगानुपात भी इस चुनाव में वर्ष 2019 से बेहतर हुआ है। पिछले चुनाव में जहां प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 928 महिलाएं थीं, जबकि इस चुनाव में यह अनुपात सुधरकर 948 महिलाओं का हो गया है। वर्ष 2019 में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात 1000 से बेहतर था, इस साल यह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है।

सेवा मतदाता बढ़े

वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव में विदेश में रहने वाले मतदाताओं की संख्या 1,18,439 हो गई है। पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 99,844 था। सर्विस वोटर यानी सेवा मतदाताओं की संख्या 2024 में 1,9,08,194 हो चुकी है जो पांच साल पहले 18,00,388 थी। इसमें सैन्य बलों, अर्द्धसैनिक बलों और देश से बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी आते हैं। इसके अलावा 10 मार्च2024 तक की मतदाता सूची के अनुसार 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 81,87,999 और 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 2,18,442 है।

पोलिंग बूथ

इस बार मतदाताओं के लिए 10,48,202 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। यह संख्या भी पिछले चुनाव के मुकाबले 1.19 फीसदी अधिक है। इस चुनाव में वोट डालने के लिए 50.5 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।

संकलन : अर्चिस मोहन

- पिछले चुनाव की तरह इस बार भी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में ही चुनाव संपन्न हो जाएगा
- उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पांच चरण में मतदान पूरा होगा। पिछले चुनाव में जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चार चरणों में मतदान हुआ था
- महाराष्ट्र में इस बार 5 चरणों में मतदान होगा, पिछले चुनाव में 4 चरणों में संपन्न हुआ था

apis®
एपीस इंडिया लिमिटेड
CIN: L51900DL1983PLC164048
पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
फोन: 011–43206650 | फैक्स: 011–25713631
ई–मेल: mail@apisindia.com वेबसाइट: www.apisindia.com

आम जनता को सूचित किया जाता है कि **एपीस इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") ने वर्ष 2019 में **एपीस मेडजूल डेट्स और एपीस खेनॅजी डेट्स** नाम से अपने दो उत्पाद लॉन्च किए थे, हालांकि प्रबंधन के निर्णय के कारण कंपनी ने **एपीस मेडजूल डेट्स को वर्ष 2020 में बंद कर दिया और एपीस खेनैजी डेट्स को साल 2021 में बंद कर दिया गया है।**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कोई हमारी सहमति के बिना बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले खजूर वाले उत्पाद बेच रहा है और आम जनता में कंपनी के ब्रांड की नकारात्मक छवि बनाना चाहता है।

हम आम जनता को सूचित करते है कि कृपया इन उत्पादों को न खरीदें क्योंकि अगर इन घटिया गुणवत्ता वाले खजूरों के सेवन से किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। कंपनी ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे हमेशा उचित बिल के साथ विश्वसनीय स्रोत से वास्तविक उत्पाद खरीदें।

कंपनी ने आम जनता की जानकारी के लिए, बाजार में कुछ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बेचे जाने वाले इन निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है। हम आम जनता की जागरुकता के लिए इन उत्पादों की तस्वीरें भी प्रकाशित कर रहे हैं।

मेडजूल डेट्स	खेनैजी डेट्स

एपीस इंडिया लिमिटेड के लिए
अमित आनंद
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 00951321